कृषि मूलम् जगत् सर्वम्

₹15

कृषि चौपाल

कृषि एवं ग्रामीण विकास को समर्पित हिंदी मासिक

वर्ष-9, अंक-4, जुलाई 2016

महिला किसानों की बढ़ती धमक

RNI Regd. No. DELHIN/2007/20953 | Postal Regd. No. DL(E)-20/5505/2016-18 | Email: krishichaupal@gmail.com | facebook: krishi chaupal | Website: krishichaupal.com

भारतीय स्टेट बैंक
हर भारतीय का बैंक

बिना जमीन बंधक किए ट्रैक्टर लोन पाइए, बस, गृह लक्ष्मी को साथ लाइए और ब्याज दर में भी छूट पाइए.

स्त्री शक्ति ट्रैक्टर लोन

स्त्री कृषि उद्यमियों का सशक्तिकरण

सह-उधारकर्ता स्त्री | जमीन बंधक नहीं
कम ब्याज दर | कम ईएमआई | शीघ्र स्वीकृति

*शर्तें लागू.

अपनी नज़दीकी एसबीआई शाखा से सम्पर्क करें
24X7 हेल्पलाइन: 1800 425 3800/1800 11 2211 (टोल फ्री) 080 26599990 या विजिट करें www.sbi.co.in

कृषि मूलम् जगत् सर्वम्
कृषि चौपाल
कृषि एवं ग्रामीण विकास को समर्पित हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष-9 ❖ अंक-4 ❖ जुलाई 2016

संपादक
महेन्द्र सिंह बोरा

संपादक मंडल
डॉ. गंगाशरण सैनी, एस. विश्वजीत प्रसाद, प्रेम सुंदरियाल, डॉ. नवीन नैनवाल, महेश पपनै

सहयोगी संपादक
ताज रावत

राजनीतिक संपादक
ललित पांडे

सहायक संपादक
खुशाल सिंह

ब्यूरो प्रमुख अल्मोड़ा
पुष्कर बिष्ट

प्रसार
दलीप जीना

डिजाइन
कल्पना प्रिंटोग्राफिक्स

संपादकीय कार्यालय
सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9,
वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092

क्षेत्रीय कार्यालय
मानपुर वेस्ट, रामपुर रोड हल्द्वानी,
जिला-नैनीताल, उत्तराखंड-263639

संपर्क: +91 9910406059,
8130956778, 9716407931

Email: krishichaupal@gmail.com
Website: krishichaupal.org

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक महेन्द्र सिंह बोरा द्वारा सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 से प्रकाशित और मयंक ऑफसेट प्रोसेस, 794/95 गुरु रामदास नगर एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 से मुद्रित।

● 'कृषि चौपाल' पत्रिका से संबंधित विवाद का निपटारा दिल्ली सीमांतर्गत सक्षम न्यायालयों में ही किया जाएगा।

● उपरोक्त सभी पद अवैतनिक हैं।

खेती में महिलाओं की उपेक्षा क्यों?

अभी महिलाओं से जुड़ा कोई दिवस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस अंक में महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल, कुछ दिन पहले देहरादून की दिव्या रावत से फेसबुक पर बात हो रही थी। ऊंची पढ़ाई-लिखाई करने के बाद दिल्ली में अच्छी-खासी नौकरी कर रही युवा दिव्या ने एक दिन अचानक फैसला लिया कि वह अपने शहर लौटकर वहीं कुछ करेगी। इस बीच उसे मशरूम की खेती के बारे में जानकारी मिली। तमाम जानकारी जुटाने के बाद दिव्या ने अंत में मशरूम की खेती करने का मन बना लिया और इससे संबंधित कोर्स करके वह दिल्ली से देहरादून लौट गयी। जैसा अन्य घरों में देखने को मिलता है कि अच्छी-खासी नौकरी कर रहे बच्चे यदि बीच में इस तरह का कोई फैसला लें तो घरवाले उसका विरोध करते हैं, जाहिर तौर पर दिव्या के साथ भी ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी जिद पर टिकी रही और आज उनकी दुनिया बदल गई है।

वर्तमान में वह न केवल स्वयं बहुत बढ़िया कारोबार कर रही हैं, बल्कि अपने आसपास की महिलाओं को भी मशरूम की खेती करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इस बातचीत के बाद हमने खेती में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने का मन बनाया। खेती में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन माहौल निराशाजनक भी नहीं है। देश में कई महिलाएं खेती में बहुत उम्दा काम कर रही हैं। अगर इन्हें प्रोत्साहन दिया जाये तो इसमें कोई शक नहीं कि देश के हालात कुछ और होंगे। एक अध्ययन के मुताबिक, यदि महिलाओं को पुरुषों के बराबर परिसंपत्तियां, कच्चा माल और सेवाओं जैसे संसाधन मिलें, तो समस्त विकासशील देशों में कृषि उत्पादन 2.5 से 4 फीसदी तक बढ़ सकता है।

इसके उलट अपने यहां होता यह है कि महिलाओं को कोई तरजीह ही नहीं दी जाती। हालांकि, अन्य क्षेत्रों में महिलाएं, पुरुषों को बराबर की टक्कर दे रही हैं, लेकिन खेती-किसानी में अब भी हालात जस के तस हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हर महिला कामकाजी है, फिर वह चाहे आय अर्जित करने के लिए श्रम करे या घर-परिवार चलाए। अगर विश्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि एक परिवार में जहां पुरुष एक दिन में औसतन 9 घंटे काम करता है, वहीं महिला 16 घंटे काम करती है। इसी तरह खेती की बात करें तो वहां भी महिलाओं के जिम्मे महत्वपूर्ण काम हैं, जिन्हें हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। पूरे भारत में महिलाएं खेती के लिए जमीन तैयार करने, बीज चुनने, अंकुरण संभालने, बुआई करने, खाद बनाने, खरपतवार निकालने, रोपाई, निराई-गुड़ाई और फसल की कटाई का काम करती हैं। इसके अलावा भी वे ऐसे कई काम करती हैं जो सीधे खेत से जुड़े हुए नहीं हैं, पर कृषिक्षेत्र से संबंधित हैं। जैसे, पशुपालन का लगभग पूरा काम महिलाओं के जिम्मे होता है। जहां मछली पालन होता है वहां उनकी भूमिका बहुत अहम होती है। पशुओं के लिए घास, पीने का पानी समेत हर काम में महिलाओं की श्रम भूमिका केंद्रीय है, लेकिन न उनका सम्मान है और न ही उन्हें मान्यता दी जाती है।

अभी तक होता यह आया है कि पुरुष किसानों को ही सशक्त करने की योजनाएं बनती रही हैं और महिलाओं को नजरअंदाज किया जाता रहा है, जबकि घर-परिवार चलाने से लेकर खेतीबाड़ी में महिलाओं की महती भूमिका होती है। लेकिन अब वक्त आ गया है जब हमें खेती में भी महिलाओं को बराबर का दर्जा देना होगा और कृषि योजनाओं को महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाना होगा। जहां तक हो सके महिला किसानों को और सुविधाएं मुहैय्या करानी होंगी। इसके बाद जो परिवर्तन दिखेगा, वह निश्चित तौर पर दर्शनीय होगा।

महेन्द्र सिंह बोरा
संपादक

इस अंक में...

कृषि समाचार	05
महिला किसान: घटती संख्या के बावजूद बढ़ती धमक	10
पंचायतों की 'चैम्पियन' महिलाएं	16
हर सवाल का जवाब नहीं है एफडीआई	18
नहीं रहे वृक्ष-मित्र राठौर	19
झाबुआ में आशा के बीज	20
ग्वार एक बहु-उपयोगी फसल	22
मछली पालन और एक्वाकल्चर में रोजगार के अवसर	24
नदी बांध योजना का वैज्ञानिक विकल्प है एमएसडीटी टेक	26
कंपनी गतिविधियां	28
राजनीतिक हलचल	32
विविधा	34

चिट्ठी-पत्री

पत्रिका अच्छी बन पाई है। कृषि व किसानों के अनुरूप सामग्री और जानकारी से भरपूर। निश्चित ही यह पत्रिका किसानों को नई-नई जानकारी से अवगत करवा कर महत्वपूर्ण साबित होगी।

-सुदर्शन

कृषि चौपाल वर्ष-9, अंक-3, जून 2016 को पढ़ा। यह कृषि के संबंध में विभिन्न तकनीकों पर ज्ञानवर्धक सामग्री प्रदान करता है। उदहारण के तौर पर मात्र 3000 में गोबर गैस प्लांट के संबंध में थोड़ी विस्तार से जानकारी देना पाठकों के हित में होता। उसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से दोहन हो रहा है। इनके विकास, संरक्षण एवं प्रबंधन पर जानकारी देना कृषि एवं कृषकों के हित में रहेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह धरोहर लाभकारी सिद्ध होगी।

-सूरज भान

आप के द्वारा भेजी गई कृषि चौपाल का अंक-3, जून 2016, किसानों के लिये बहुत उपयोगी पत्रिका है। हमारी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं! पत्रिका की निरंतरता बनाये रखें तथा इस संस्थान को भी अपनी मेलिंग लिस्ट में शामिल करके अनुगृहीत करें!

-प्रभारी पुस्तकालय, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल

'कृषि चौपाल' के जून अंक का संपादकीय 'कुछ और कहती है जमीनी हकीकत' रोंगटे खड़े करने वाला है। मोहनी की दुर्दशा की कहानी पूरी नहीं पढ़ी। थोड़ा पढ़कर ही आसूं आ गए। सीधे नाना पाटेकर के बयान पर आ गया। नाना ने बिलकुल सटीक बात कही है कि यदि केंद्र सरकार ने जमीनी स्तर पर कुछ किया होता, तो उसे एक हजार करोड़ रुपये विज्ञापन पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, यूं उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनके मंत्री उनकी तरह सक्रिय नहीं हैं। अब मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में बदलाव कर लिए हैं, उम्मीद है कि अब उनकी सरकार बढ़िया काम करेगी।

-कप्तान सोबन, करनाल, हरियाणा

नए अंक का संपादकीय पढ़ा। वास्तव में ये मोहिनी के घर की कहानी नहीं है, बल्कि लगभग हर किसान का यही हाल है। अभी कुछ महीने पहले हमारे इलाके में भी कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि सभी पर मोटा कर्ज चढ़ गया था। आपने मंत्री जी का इंटरव्यू छापा, अच्छा लगा, लेकिन हम जैसे किसानों का भी इंटरव्यू लो, ताकि हमारी दुर्दशा मंत्री जी तक पहुंच पाए।

-रामभरोसे यादव, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश

पत्रिका के ताजा अंक के आखिरी पन्ने में 'घाघ की कहावतें' बहुत पसंद आई। मैं एक किसान हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने घाघ के बारे में पहले नहीं सुना था। आपकी पत्रिका में जब घाघ को पढ़ा और इस संबंध में अपने आस-पड़ोस में चर्चा की, तब मालूम चला कि घाघ बहुत बढ़े घाघ थे। वे किसानों और खेतीबाड़ी के महान कवि थे। वैसे बाजार में उन पर कोई किताब नहीं मिली, लेकिन दुकानदार ने कहा है कि वह किताब मंगवा देगा। फिर भी आपसे अनुरोध है कि बीच-बीच में आप पत्रिका में घाघ की कहावतें प्रकाशित करते रहिएगा।

-सुखविंदर सिंह, होशियारपुर, पंजाब

जून अंक की आवरण कथा 'जल: आज और कल' सही समय पर प्रकाशित की गई है। सरकार के साथ ही अब आम लोगों को भी जल संचय के बारे में गहराई से सोचना होगा, क्योंकि जल है तो कल है। पिछले वर्षों में सूखे की वजह से हम कितने व्याकुल हुए, ये किसी से छिपा नहीं है। कई-कई इलाकों में खेतों की छोड़ दीजिये, लोगों और जानवरों के पीने तक पानी नहीं था। इसके बावजूद अगर हम पानी की प्रति लापरवाही बरतेंगे, तो हमसे निरा मूर्ख कोई और नहीं होगा। हालांकि पत्रिका में जल समस्या पर तो चर्चा की है, लेकिन जल संचय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। सिर्फ देवास मॉडल अपनाने की बात भर दी गयी है। जिलाधीश से जलाधीश बने देवास के डीएम साहब बधाई के पात्र हैं, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम कैसे किया, इसका प्रमुखता से उल्लेख भविष्य में जरूर प्रकाशित करें, ताकि उनके द्वारा शुरू की गई मुहिम देशभर में फैल सके।

-उमेश यादव, मेरठ, उत्तर प्रदेश

जून का अंक ई-मेल से मिला। पूरी पत्रिका पठनीय है, लेकिन कृषि मंत्री मोहन भाई कुंदरिया का साक्षात्कार और बटरोही की रिपोर्ट 'पिताजी का काण घा और रामदेव का एलोवेरा' ज्ञानवर्धक हैं।

-डॉ. जगजीत सिंह, पंजाब यूनिवर्सिटी

जून 2016 के अंक में दिनेश जोशी की जानकारी 'धान के रोग एवं उनसे बचाव' विस्तृत व सम्पूर्ण है। इन आलेखों का लाभ सभी किसान भाइयों को उठाना चाहिए। अगर ऐसी जानकारी किसानों को समय रहते मिल जाये, तो वे भी फसल में रोग लगने से पहले सतर्क हो जाये और उनका निदान खोज लें।

-प्रशांत सिंह, कटिहार, बिहार

ई-मेल के जरिये पत्रिका निरन्तर मिल रही है। बकायदा में इसे आगे 25-50 लोगों को और भेज देता हूं। मेरा मानना है कि ऐसी शानदार पत्रिका सभी की नजरों से गुजरनी चाहिए।

-ओंकार नाथ, नई दिल्ली

जून अंक में प्रकाशित 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: किसानों के सवालों के जवाब' बहुत ही जानकारी भरा है। इससे फसल बीमा योजना को लेकर मन की शंकाओं दूर हो गयीं। आपने हर संभावित सवाल और उसका जवाब आसान तरीके से प्रकाशित किया है। डॉ. महर उद्दीन खां का लेख 'संकर बीजों का बीजगणित' भी अच्छा लेख है। ज्यादा से ज्यादा फसल के चक्कर में किसानों ने अपनी जमीन की बुरी गत कर दी है और हम विदेशी हाथों में खेल रहे हैं। यही हाल रहा तो एक दिन हमारे परंपरागत बीज विलुप्त हो जाएंगे।

-सुखविंदर सिंह, बाजपुर, उत्तराखंड

सत्ता बदली तो बदल गये सुर

स्वामीनाथन आयोग की जिस रिपोर्ट को लागू करने का वादा कर बीजेपी सत्ता में आई थी, उसे लेकर सरकार कितनी गंभीर है इस बात का अंदाजा आरटीआई से मिली ताजा जानकारी से लगाया जा सकता है।

दरअसल समालखा के आरटीआई कार्यकर्ता पी.पी. कपूर ने स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुद्दे पर केंद्र और हरियाणा सरकार से जानकारी मांगी। जवाब में केन्द्र सरकार ने कहा कि लागत मूल्य पर 50 फीसदी बढ़ोतरी से मंडी में दिक्कतें आ सकती हैं। लिहाजा इसे लागू करना अभी संभव नहीं है। वहीं हरियाणा सरकार ने तो आयोग की सिफारिशें उनके पास होने से ही इनकार कर दिया है।

स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसानों को फसल लागत मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना था। समालखा के आरटीआई एक्टिविस्ट पी.पी. कपूर ने गत 7 मार्च को प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव हरियाणा कार्यालय में अलग-अलग दो आरटीआई आवेदन भेजकर सूचना मांगी थी। इसमें पूछा था कि किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य देने के बारे में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए केन्द्र व हरियाणा सरकार ने क्या कार्रवाई की है? भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की उप-सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी सुशीला अनंत ने गत 6 अप्रैल के अपने पत्र द्वारा जो सूचना दी है वह बेहद चौंकाने वाली है।

उप-सचिव सुशीला अनंत ने बताया है कि स्वामीनाथन आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से संबंधित सिफारिश को केन्द्र सरकार द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग (एमएसपी) द्वारा संबंध घटकों की किस्म पर विचार करते हुए वस्तुपूरक मानदंड पर की जाती है। अत: लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि करने से मंडी में विकृति आ सकती है। उपसचिव सुशीला अनंत ने यह भी बताया कि स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय किसान नीति का विस्तृत मसौदा प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर राष्ट्रीय किसान नीति 2007 बनी थी जो कि अभी प्रचलन में है।

केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई अधिकांश स्कीमें या कार्यक्रम राष्ट्रीय किसान नीति 2007 के अनुरूप हैं। दूसरी ओर हरिणाा सरकार के कृषि निदेशक कार्यालय पंचकूला के राज्य जन सूचना अधिकारी ने अपने 18 अप्रैल के पत्र द्वारा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को हरियाणा में लागू करने का कोई लेखा-जोखा उनके पास नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया।

विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने इस मुद्दे को खूब भुनाया। खुद ओम प्रकाश धनखड़ इस मुद्दे पर कई बार सड़कों पर उतरे लेकिन सत्ता बदली तो नेताओं के सुर भी बदल गए।

पंजाब में गहराने लगा है खेती पर संकट

किसान बासमती चावल और कपास की खेती छोड़ कर गेहूं व दूसरे किस्म के धान की खेती करने में जुटे हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में आती हैं। पंजाब में समय-समय पर खेती पर संकट के बादल मंडराते रहते हैं। इस बार यह संकट खेती की जमीन के किराये में भारी गिरावट के रूप में सामने आया है। इस मौसम में राज्य के किसान ऐसी फसल की खेती करने से बच रहे हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में नहीं आती और वे पारम्परिक धान की खेती की ओर लौट रहे हैं।

कपास की खेती में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी जा रही है। कमोबेश पूरे राज्य में यही हालत है, कुछ एक अपवाद को छोड़कर खेतों के किराये में करीब 40 फीसदी की गिरावट देखी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले दो साल में बासमती पूसा-1121 किस्म व आलू की गिरती कीमतों के चलते खेती की जमीन के किराये में कमी आई है। यह फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य की श्रेणी में नहीं आती है और जिन किसानों ने इनकी खेती की थी, उन्हें भारी घाटा उठाना पड़ा है। किसान अपनी लागत भी नहीं वसूल सके हैं।

पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला के कृषि अर्थशास्त्र विशेषज्ञ प्रो. ज्ञान सिंह के अनुसार यह बाजार में माल नहीं उठने और आय में गिरावट का नतीजा है। रिपोर्ट के मुताबिक पूसा-1121 बासमती चावल में गत वर्ष 1600 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ देखा गया जबकि उससे पूर्व के पिछले दो वर्षों में ये आंकड़े क्रमश: 3,000 से 3,300 रुपए और 5,000 से 5100 रुपए प्रति क्विंटल था।

प्रो. सिंह कहते हैं कि मालवा जैसे इलाके में जमीन का किराया जहां 70,000 रुपए प्रति एकड़ था, वहां अब 30,000 से 45,000 रुपये प्रति एकड़ रह गया है। शिवालिक जैसे निचले पहाड़ी इलाके में जमीन का किराया 2,000 से 5,000 रुपये प्रति एकड़ है। उन्होंने अपेक्षित किराये की ओर संकेत करते हुए बताया कि रामपुराफुल इलाके में खेत का किराया 60,000 रुपये प्रति एकड़ है। यहां के किसान को आलू के सही दाम मिले और उनका कहना है कि वे आलू की ही फसल उगाना जारी रखेंगे।

ग्रामीण अनुसंधान एवं औद्योगिक विकास केंद्र (सीआरआरआईडी), चंडीगढ़ के विशेषज्ञ शेर सिंह सांगवान के अनुसार हाल के वर्षों में पंजाब और हरियाणा को किराए और खेती के तौर-तरीकों में प्रतिकूल परिस्थितियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। जिन मध्यमवर्गीय किसानों के पास संसाधन होते हैं वे अपने इन्हीं यंत्रों का प्रयोग कम खर्चे पर किराये वाली जमीनों की जुताई के लिए कर सकते हैं। किराये की यहपद्धति अस्सी के दशक के मध्य में शुरू हुई थी।

बीहड़ में फूलों की खेती, इत्र-रूह से महकेगा देश

चंबल का नाम सुनते ही जहां लोगों की रूह कांप जाती है, वहीं इस चंबल में अब गुलाब रूह तैयार हो रही है। यहां अब डकैतों की गोलियां नहीं चलतीं, बल्कि फूलों की खेती होती है और इत्र बनाया जा रहा है। यहां खेती

के साथ एक किसान परिवार ने सेंट बनाने की फैक्टरी खोल ली है, जो किसानों को फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इससे किसानों का रुझान फूलों की अतिरिक्त पैदावार की ओर बढ़ रहा है।

बड़ोखर निवासी सुशील राजौरिया ने यहां इत्र बनाने की फैक्टरी लगाई है। वे 12 बीघा जमीन पर गुलाब पैदा करके उसका इत्र बनाते आ रहे हैं और उसका व्यवसाय करते हैं। वे बताते हैं कि एक बीघा में पांच क्विंटल के करीब गुलाब पैदा होता है। जबकि एक क्विंटल गुलाब में से 18 ग्राम तक रूह निकलती है। सुगंधित तेल निर्माण में विशेषज्ञ संतोष शर्मा के मुताबिक एक ग्राम रूह की कीमत 1000 रुपए तक है।

रूह बनाने के लिए सबसे पहले कॉपर के देग में 35 किलोग्राम गुलाब के फूल व इतना ही पानी भरते हैं। देग को तीन घंटे तक उबाला जाता है जिसमें ऊपर बांस का पाइप लगाते हैं। तपिश से गुलाब से रूह निकलती है जो पाइप से रिसीवर में एकत्रित होती है। 35 किलो गुलाब से पांच लीटर रूह मिक्स पानी भाप के रूप में निकलता है। इसी तरह उसे फिर से तपाते हैं तो अंत में रूह निकलती है, जो विशुद्ध इत्र होता है।

इसी प्रकार गुलाब का स्प्रे सेंट भी तैयार किया जाता है। गुलाब जल भी तैयार होता है। इसके अलावा गुलाब का रूम स्प्रे भी बनाया जाता है।

चीन तीन महीने में खरीदेगा और दस हजार टन जीरा

एशिया की सबसे बड़ी जीरा मंडी ऊंझा में चीन की पिछले तीन दिन से खरीद पूछपरख देखी जा रही है। चीन भारत से अब तक तकरीबन 18-20 हजार टन जीरे की खरीद कर चुका है। अगले तीन महीने में चीन भारत से दस हजार टन जीरे की और खरीद करेगा। इसके अलावा बकरीद के लिए आने वाले समय में मध्य पूर्व देशों से भी दस हजार टन जीरे की खरीद निकलने की संभावना है।

ऊंझा के जीरा निर्यातकों ने बताया कि भारत से चीन को मार्च महीने में तीन हजार टन, अप्रैल में सात हजार टन और मई में भी सात हजार टन जीरे का निर्यात हुआ। यह जीरा चीन में डिलीवर हो चुका है। इसके अलावा भारतीय निर्यातकों के पास फारवर्ड सौदे चार हजार टन के हैं जिनकी डिलीवरी आने वाले दिनों में चीन को होगी। चीन की ओर से ऊंझा बाजार में पूछपरख चल रही है और जिस तरह का कारोबार होने के आसार हैं उसमें चीन अगले तीन महीने में भारत से तकरीबन दस हजार टन जीरे की खरीद करेगा।

रमजान के बाद इस्लामिक देशों की भी बकरीद के लिए जीरे की मांग निकलेगी। मध्य पूर्व देशों की यह मांग भी तकरीबन दस हजार टन रहने की संभावना है। इस तरह अगले तीन महीनों (जून-अगस्त) में भारत का जीरा निर्यात चीन एवं मध्य पूर्व देशों को 20 हजार टन के आसपास रह सकता है। यद्यपि, वैश्विक स्तर पर इस समय भारत का जीरा निर्यात सुस्त है लेकिन अब चीन के मैदान में आने से निर्यातकों में खुशी देखी जा रही है।

बता दें कि चीन वर्ष 2008-2009-2010 तक खुद भी जीरे का निर्यात करता था और वहां इसकी पैदावार 30-35 हजार टन थी लेकिन जीरा उत्पादक इलाकों में आई औद्योगिक क्रांति से वहां जीरे की पैदावार सीमित रह गई और खेत खत्म हो गए। चीन में इस साल जीरे का उत्पादन 5-10 हजार टन पैदा होने की उम्मीद है। चीन की नई फसल जून अंत-जुलाई शुरुआत में आएगी। लेकिन इस जीरे का इस्तेमाल केवल परंपरागत चीनी व्यंजन और हर्बल उत्पादों में ही किया जा सकता है। जबकि अब चीन में खाने की आदतें बदलने से जीरे की मांग 30-35 हजार टन सालाना पहुंच गई है। इस मांग का विश्लेषण करें तो यह साफ है कि चीन भारत से जीरे की खरीद करता रहेगा।

चीन को अच्छी मात्रा में जीरे का निर्यात करने वाले एक निर्यातक ने कहा कि यदि भारत में जीरे के दाम बढ़ने और अगली फसल को लेकर कोई अंदेशा हुआ तो चीन अपनी मांग से भी अधिक जीरे की खरीद कर सकता है क्योंकि उसे इसका स्टोरेज करने में कोई परहेज नहीं है। भारत में इस साल ला नीनो आने की संभावना जताई जा रही है, ऐसे में फसल को लेकर कोई आशंका सामने आई तो चीन एक साल का एवरेज स्टॉक कर सकता है। चीन भारत से 99।5 सिंगापुर क्वॉलिटी जीरे की ही खरीद करता है और इसके सौदे 2480-2500 अमरीकी डॉलर प्रति टन सीएंडएफ पर हो रहे हैं। इन भावों को देखें तो चीन 25-30 डॉलर प्रति टन प्रीमियम अदा कर रहा है। जीरे के दाम घरेलू बाजार में यदि स्थिर रहते हैं तो इस साल भारत का कुल जीरा निर्यात 90 हजार से एक लाख टन तक पहुंच सकता है, क्योंकि दाम बढ़ने पर मांग का प्रभावित होना स्वाभाविक है।

जुलाई महीने में सवा करोड़ पौधे लगायेगी झारखंड सरकार

जुलाई माह से पूरे राज्य में एक करोड़ पौंधे व 20 लाख फलदार पौधारोपण किया जाएगा। यह निर्णय प्रधानमंत्री के साथ पिछले दिनों हुई बैठक में लिया गया। फलदार पौधे डोबा के आसपास लगेंगे। यह कदम जल संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया जा रहा है। जल संरक्षण के लिए सरकार ने पहल कर दी है। लेकिन यह तभी सफल होगा जब राज्य का एक-एक आदमी इसके प्रति संवेदनशील बने। उक्त बातें झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने होटल बीएनआर चाणक्या में जल संरक्षण पर आयोजित कार्यशाला में कहीं। कार्यशाला का आयोजन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार एवं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था।

रघुवर दास ने कहा कि जल सस्ता है, लेकिन बहुमूल्य संसाधन है। अगर इसका सही ढंग से उपयोग नहीं हुआ तो भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। कुदरत ने पृथ्वी को पर्याप्त मात्रा में पानी दिया है लेकिन इसके संचय और संरक्षण के प्रति हम गंभीरता नहीं दिखा पाते हैं, परिणामस्वरूप जल संकट हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि इससे पेयजल, सिंचाई समेत उद्योग-धंधे प्रभावित होते हैं। यह कार्यशाला लोगों में सकारात्मक संदेश का संचार करेगी। हमें जल संरक्षण को जल आंदोलन का रूप देकर राष्ट्र स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना

चाहिए। इसका समाधान जागरूकता ही है। सरकार अकेले यह काम नहीं कर सकती है। सभी को मिलकर काम करना होगा। सभी की सक्रिय भागीदारी ही इसका समाधान है।

रघुवर दास ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता है गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और शहर का पानी शहर में रहे। सरकार ने दो महीने में एक लाख डोबा का निर्माण करेगी। हजारों डोबा बनकर तैयार हैं। सार्वजनिक और निजी तालाबों के जीर्णोद्धार का काम जल संवर्धण के लिए हो रहा है। हमारी मंशा जल के प्रति गंभीर है। यही वजह है कि नए एवं पुराने भवनों में जल संचय हेतु दिशा निर्देश पूर्व में ही जारी कर दिया गया है। उन्होंने लोगों को कालीदास के मेघदूत की कहानी पर विचार करने की सलाह दी, ताकि जल संरक्षण पर बल दिया जा सके।

बंगाल में कृषि योजना के रूप में फिर लौटा चिटफंड

सारदा घोटाले के खुलासे के बाद कई साल तक मरणासन्न रहा चिटफंड पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार 'कृषि योजनाओं' के रूप में वापस लौट आया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इन चिटफंड योजनाओं के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। ये योजनाएं बंगाल के विभिन्न हिस्सों में छोटे स्तर पर चल रही हैं।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री साधन पांडे ने बताया कि एक साल से अधिक समय से हमें इस बारे में बहुत सी शिकायतें मिल रही हैं कि निवेशकों को कृषि योजनाओं में लगाया गया। उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है या इसका गबन कर लिया गया है। खासकर ग्रामीण बंगाल से ये शिकायतें मिल रही हैं। मंत्री ने कहा कि कुछ चिटफंड योजनाओं में आलू की खरीद पर निवेश पर भारी मुनाफे का वायदा किया गया तो कुछ अन्य में वृक्षारोपण या मुर्गी पालन पर निवेश करने से भारी मुनाफा मिलने का वायदा किया गया। मंत्री के अनुसार, ये पोंजी योजनाएं सारदा या अन्य बड़ी चिटफंड कंपनियों की तरह नहीं हैं जो फिलहाल सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की निगरानी में हैं। अप्रैल 2013 में सारदा घोटाला सामने आने के बाद कई पोंजी योजनाएं बंद हो गई थीं और चिटफंड कंपनियों को अपना बोरिया-बिस्तर समेटना पड़ा था क्योंकि केंद्र और राज्य की एजेंसियों ने ठगी के शिकार हुए लाखों निवेशकों के विरोध के बीच इस तरह की कंपनियों पर चाबुक चलाया था। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार, ये चिटफंड कंपनियां इतने छोटे स्तर पर चल रही हैं कि कई बार स्थानीय प्रशासन के लिए इन्हें ढूंढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। पांडे ने कहा है कि उनका विभाग गरीब और भोले-भाले ग्रामीण लोगों को इन योजनाओं में निवेश के जोखिमों के बारे में अवगत करा रहा है।

किसान ने बेटे को खेत में जोता

महाराष्ट्र के अकोला में बरसात हो रही है, कई किसानों के लिए ये खुशखबरी है लेकिन कुछ के लिए मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। जिले के दहीगांव के रहने वाले अरुण गावंडे उनमें से एक हैं। बैल कर्ज पर ले नहीं सकते इसलिये खेत जोतने में बेटे की मदद ले रहे हैं।

खेती में मदद के लिये अरुण ने 12वीं में पढ़ने वाले अपने बेटे ऋषिकेश को वापस बुला लिया है। वह फिलहाल स्कूल में नहीं खेत में है। खेत जोतने के लिए बैल की जगह खुद मशक्कत कर रहा है। दो एकड़ के खेत में सोयाबीन की बुवाई करनी है लेकिन पिता के पास किराये पर बैल लेने के पैसे नहीं थे सो बेटे को जोत दिया।

गांव में बरसात चार साल बाद आई है। इस उम्मीद में बेटा पिता के साथ पसीना बहा रहा है कि बारिश के साथ राहत की फसल उगेगी। ऋषिकेश गावंडे का कहना है कि वह पढ़ना चाहता है लेकिन पिताजी के पास पैसे नहीं हैं। ऋषिकेश का कहना है, ''पिताजी ने बोला घर आ जाओ पैसे नहीं हैं, पैसे कैसे देंगे पढ़ने के लिये। दो-तीन दिन से खेत जोत रहा हूं। बारिश आई बीज सड़ गया तो दुबारा कर रहा हूं। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तीन बार अटैक आया 2009 में।''

अरुण गावंडे ने महाराष्ट्र बैंक से 36 हजार का कर्ज लिया था। तीन साल से सूखे की वजह से फसल बर्बाद हो रही है, सो कर्ज चुका नहीं सके। प्रशासन ने खरीफ की बुवाई के लिये कर्ज चुकाने की अनुसूची फिर से बनाने की बात कही थी, लेकिन वक्त पर पैसे मिले नहीं। बादल आ गये, ऐसे में बीज और खेत जेब की राह तकने को तैयार नहीं थे। अरुण ने बेटे को बैल बनाने की बात पर हामी भरते हुए कहा कि 'बेटे के बैल बनाया क्योंकि पैसा नहीं आया, बीज लाने के पैसे नहीं हैं, बैल वालों को क्या देंगे? मां की दवा लानी पड़ती है, परिस्थिति ऐसी नहीं है। बच्चे और मैं मिलकर जुताई कर लेंगे। तीन साल हो गये, 2007 में पिता गुजर गये, कोई पैसा नहीं है। पूरी जवाबदेही मेरे ऊपर है।'

प्रशासन हकीकत जानने के बाद इस मामले में अरुण के परिवार को मदद का भरोसा दे रहा है। अकोला में एसडीओ राजस्व संजय खडसे ने कहा, 'हमने जांच की है, तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई है प्रशासन की तरफ से जो भी मदद होगी हम करेंगे।'

2015 में महाराष्ट्र में लगभग 3000 किसानों ने खुदकुशी की थी। अप्रैल से पहले इस साल भी औसतन तीन किसान हर रोज खेती या उससे जुड़ी दिक्कतों की वजह से मौत को गले लगा रहे थे। इन मामलों में कार्रवाई फौरन हो तो राहत मिले, नहीं तो राहत ढूंढने पता नहीं कितने बच्चों को बस्ता छोड़ ऋषिकेश की तहर खेत में जुतना पड़ेगा।

खाट से ही जोत डाला खेत

महाराष्ट्र के जलगांव जिले के खडकी बुद्रूक गांव में रहने वाले एक किसान ने आर्थिक तंगी और साधनों की कमी के चलते खाट से ही पूरा खेत जोत दिया। हालांकि इस खेत का मालिक किसान नहीं है। वह किसी और के नाम है, लेकिन ये खेत किसान ने किराए पर लिया है। महाराष्ट्र के रहने वाले इस किसान का नाम विठोबा मांडोले है। जिस गांव में विठोबा रहते हैं वहां की जमीन सूखे से ग्रस्त है।

कई सालों तक विठोबा ने आसपास के खेतों में मजदूरी की, लेकिन उनका मानना था कि इससे तरक्की नहीं होगी, जिसके चलते उन्होंने खेत किराए पर ले लिया, लेकिन विठोबा के

पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे वह औजार या बैल खरीद पाए। ऐसे में उसने हिम्मत नहीं हारी और जुगाड़ लगाया। इसके बाद किसान विठोबा को खेत जोतने की एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपनी खाट को हल बनाया और उस पर बड़े बोल्डर रख खुद खींचकर तीन एकड़ खेत जोत दिया। खेत जोतते हुए उनकी फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।

हर किसान परिवार पर 47,000 रुपए का कर्ज

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2013 में किए गए स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) के अनुसार जिस दिन किसान परिवारों पर कर्ज के आंकड़े लिए गए थे, उस दिन प्रत्येक कृषक परिवार पर औसतन लगभग 47,000 रुपए कर्ज होने का अनुमान लगाया गया है।

इस ऋण में संस्थागत संस्थानों तथा सेठ-साहूकारों से लिए गए कर्ज भी शामिल हैं। सर्वेक्षण के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 52 प्रतिशत किसान परिवारों के कर्ज के बोझ में दबे होने का अनुमान लगाया गया। कम जोत के किसान परिवार पर कम कर्ज का भार है जबकि बड़े किसान परिवारों पर अधिक कर्ज है। कम जमीन वाले 41.9 प्रतिशत किसानों पर कर्ज हैं, जबकि 10 हैक्टेयर से अधिक जमीन वाले 78.7 प्रतिशत किसान परिवार कर्जदार हैं। एक हैक्टेयर से कम जमीन वाले किसान परिवार पर औसतन 31,100 रुपए का ऋण है जबकि 10 हैक्टेयर से अधिक जमीन जोतने वाले किसान परिवार लगभग 2,90,300 रुपए के कर्जदार हैं। एक हैक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों ने संस्थागत संस्थानों अर्थात सरकार, सहकारिता समितियों और बैंकों से 15 प्रतिशत कर्ज लिया है जबकि 10 हैक्टेयर से अधिक जमीन रखने वाले किसानों ने इन संस्थानों से 79 प्रतिशत कर्ज लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर किसानों ने 60 प्रतिशत ऋण संस्थागत संस्थानों से लिया है। बैंकों ने 42.9 प्रतिशत ऋण दिया है जबकि सहकारिता समितियों ने 14.8 प्रतिशत तथा सरकार ने 2.1 प्रतिशत ऋण दिया है। गैर-संस्थागत संस्थानों या सेठ-साहूकारों ने 25.8 प्रतिशत कर्ज किसानों को दिया है। वर्ष 2013 में किए गए सर्वेक्षण (एसएएस) में देश में 9 करोड़ 2 लाख किसान परिवार होने का अनुमान लगाया गया है। लगभग 69 प्रतिशत कृषक परिवारों के पास एक हैक्टेयर से कम जमीन है। केवल 0.4 प्रतिशत किसान परिवारों के पास 10 हैक्टेयर या इससे अधिक जमीन है। सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर 0.1 प्रतिशत किसान परिवार भूमिहीन पाए गए जबकि 6.7 प्रतिशत परिवारों के पास केवल मकान की ही जमीन थी। कुल 92.6 प्रतिशत किसान परिवारों के पास मकान के अलावा थोड़ी-बहुत जमीन है।

मोबाइल से बुक होगा ट्रैक्टर

सरकार को अगर नीति आयोग का एक सुझाव रास आया तो वह दिन दूर नहीं जब गांव की चौपाल पर बैठे किसान अपने मोबाइल फोन से ओला और उबर टैक्सी की तर्ज पर ट्रैक्टर बुक कर सकेंगे। कुछ ही मिनट में ट्रैक्टर उनके खेत पर पहुंच कर जुताई-बुवाई या फसल कटाई जैसा काम शुरू कर देगा। ऐसा होने पर बहुत से किसानों को भारी भरकम कर्ज लेकर ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही राज्यों को मंडी कानूनों में बदलाव कर दुग्ध संग्रह की तर्ज पर गांवों से फल और सब्जियों के संग्रह की पहल भी की जाएगी।

ये सुझाव नीति आयोग में कृषि मामलों के प्रभारी सदस्य रमेश चंद ने दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि जुलाई के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इन सुझावों पर चर्चा हो सकती है। राज्यों के मुख्यमंत्री गवर्निंग काउंसिल में सदस्य शामिल हैं। काउंसिल की यह बैठक एक साल से अधिक समय बाद हो रही है, इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है।

गवर्निंग काउंसिल की बैठक में जिन विषयों पर चर्चा होनी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय वर्ष 2022 तक कृषि आय दोगुनी करना है। बताया जाता है कि रमेश चंद इस विषय पर पीएम और मुख्यमंत्रियों के समक्ष एक प्रजेंटेशन देंगे। ऐसे में जो सुझाव उन्होंने दिए उनका खासा महत्व है।

इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा रिपोर्ट तथा पंचवर्षीय योजनाओं की जगह बनने वाली सप्तवर्षीय योजनाओं, तीन वर्षीय कार्ययोजनाओं और 15 वर्षीय विजन दस्तावेज के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा गरीबी, कृषि, स्वच्छ भारत तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा के लिए गठित की गई नीति आयोग की समितियों की सिफारिशों और उनके क्रियान्वयन पर भी चर्चा की जाएगी।

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले साल हुई इस बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इससे दूरी बना ली थी। ऐसे में देखना होगा कि इस बार इस बैठक में कितने राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।

किराये पर ट्रैक्टर देने के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन

सूत्रों का कहना है कि सरकार नाबार्ड के माध्यम से वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर ओला और उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि मशीनरी और उपकरण मुहैया कराने के लिए उद्योग जगत तथा निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी। फिलहाल ईएम-3 एग्रीसर्विसेज प्राइवेट लिमिटंड 'समाधान' नाम से मध्य प्रदेश में ऐसी ही सुविधा मुहैया कराती है। लघु और मझोले किसान 'यूज एंड पे' मॉडल पर कृषि मशीनरी और ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह उन्हें लेटेस्ट टैक्नॉलाजी के लिए बड़ा निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती।

उत्तराखंड की जमीन कृषि उत्पादन में फिसड्डी

नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार उत्तराखंड की जमीन कृषि संबंधी उत्पादन में फिसड्डी साबित हो रही है। कृषि भूमि की उपयोगिता को लेकर जारी किए गए देश के 581 जिलों के आंकड़ों में राज्य के पांच जिले काफी पीछे साबित हो रहे हैं। इनमें ऊधमसिंह नगर (59), हरिद्वार (71) और नैनीताल (130) की ही स्थिति बेहतर है जबकि अल्मोड़ा (527), पौड़ी (519), देहरादून (230) पायदान पर खड़ा है। प्रदेश के अन्य जिलों की तस्वीर भी बेहतर नजर नहीं आती।

दूसरी तरफ राज्य की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राज्य की कुल आबादी का 75 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण है, जो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। 55.66 लाख हेक्टेअर क्षेत्रफल में 34.66 हेक्टेअर वन क्षेत्र है। बंजर भूमि पर्वतीय क्षेत्र में 4.63 लाख हेक्टेअर है और मैदानी क्षेत्र में 35,338 हेक्टेअर है।

राज्य की लगभग 5,91,418 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की जा रही है। यमुना, भागीरथी, भीलांगना, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरयू, गौरी, कोसी और काली नदियों से सिंचाई व्यवस्था की जाती है।

जंगली सुअर और बंदरों के झुंड फसलें चौपट कर रहे हैं तो कहीं हाथी फसल को रौंद रहे हैं। उत्तराखंड में हर माह 20 हेक्टेयर खेत तबाह हो रहे हैं।

उस पार खेती, इस पार किसान

अमृतसर के सीमावर्ती गांवों के किसान हमेशा ही मुसीबतें झेलते आए हैं लेकिन सीमा सुरक्षा बल का सहयोग नहीं मिलने के कारण भारतीय सीमा के अंदर लगी कंटीली बाड़ के उस पार खेती करना किसानों के लिए मुसीबत का सबब बना गया है। सुरक्षा की दृष्टि से सीमा पर कंटीली बाड़ लगाने से आसपास के गांवों की लगभग 2500 एकड़ जमीन बाड़ के उस पार रह गई है जहां खेती करने के लिए किसान सीमा सुरक्षा बल पर निर्भर रहते हैं। सीमावर्ती गांव कक्कड़ के मुखिया शिवराज सिंह ने बताया कि बीएसएफ किसानों से सहयोग नहीं कर रही है जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है।

उन्होंने बताया कि कंटीली बाड़ के उस पार जाने का समय सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित किया गया है लेकिन बीएसएफ के अधिकारी अपनी इच्छा अनुसार ही उधर जाने की अनुमति सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक ही देते हैं।

किसान रूलदा सिंह ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार के समय से सरकार बाड़ के पार जमीन के लिए 1997 से 2000 तक 2500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देती थी लेकिन साल 2000 के बाद इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बीएसएफ द्वारा तीन फुट से ज्यादा ऊंची फसल पर प्रतिबंध लगाने के कारण यहां केवल गेहूं और धान की ही खेती की जाती है। नौशहरा के किसान मुख्तियार सिंह ने बताया कि उसके खेत तीनों तरफ से कंटीली बाड़ से घिरे हुए हैं। बीएसएफ द्वारा बरीकी से जांच करने में काफी समय बर्बाद हो जाता है जिसके कारण वह दो-तीन घंटे ही खेतों में काम कर पाते हैं।

उन्होंने बताया कि कई बार तो पाकिस्तान की ओर से राकेट दागे जाते हैं जिस कारण फसल का कार्य बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ता है। गांव राजी, कस्सोवाल और सारण की लगभग दस हजार एकड़ जमीन रावी दरिया और कंटीली बाड़ के बीच में है। किसानों ने बताया कि बाड़ के पार खेती अब लाभदायक धंधा नहीं रहा है। न तो कोई उनकी जमीन खरीदता है तथा न ही ठेके पर लेने को तैयार है। किसान शिवराज सिंह ने बताया कि उन्होंने बीएसएफ मुख्यालय के कमांडर को अपनी मुश्किलों और बीएसएफ के रवैये के संबंध में पत्र लिखकर बताया है जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने मांग की है कि सरकार उनकी समस्याओं का कोई स्थाई हल निकाले।

कोई भी रईस शख्स या सरकार बोली लगाकर गांव खरीद सकती है

भारत में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां के लोगों ने ही उन्हें बेचने का ऐलान कर दिया है। भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे इन चार गांवों के किसानों ने अपनी बदहाली से तंग आकार अपने गांवों को बेच देना का फैसला लिया है। गांव के लोगों ने इसके लिए बाकायदा पोस्टर छपवाए हैं जिन पर लिखा है- 'कोई भी रईस शख्स, टाटा, अंबानी या सरकार बोली लगाकर गांव खरीद सकती है।'

पंजाब के इन गांवों का नाम है फाजिल्का के केरियां, मुठियां वाली, चानन वाला और चुल्हड़ी। इन गांवों की ज्यादातर जमीन बंजर हो चुकी है और 99 प्रतिशत किसान कर्ज में डूबे हैं। उधर पंजाब सरकार को जैसे ही इस घोषणा के बारे में पता चला तो उसने लोगों का हालचाल लेने की जगह इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है। पंजाब के मंत्री और लोकल एमएलए सुरजीत जियाणी के मुताबिक ये सब विपक्षी पार्टी का कारनामा है।

इन चारों गांवों के किसानों की शिकायत है कि सीमा से सटे होने के चलते सरकार इन पर ध्यान नहीं देती। किसानों की मानें तो ढाई महीनों से नहर में पानी नहीं आया जिसके चलते पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। जिन किसानों ने बैंक से लोन लिया था उनके लिए खुदखुशी का ही रास्ता बचा है। इन सब दिक्कतों के चलते गांव वालों ने इन चारों गांवों को बेचने का फैसला लिया है। किसानों का आरोप है कि गांव में आज तक सेकेंडरी स्कूल और अस्पताल की सुविधा भी नहीं है।

जिस संजीवनी को हनुमानजी भी नहीं खोज सके उसे उत्तराखंड सरकार खोजेगी

उत्तराखंड सरकार ने संजीवनी बूटी की तलाश में केंद्र सरकार से मदद मांगी है। रामायण में वर्णित मिथकीय औषधि संजीवनी के प्रयोग से राम के मूर्छित भाई लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की गई थी। अभी तक ऐसी किसी जड़ी-बूटी का पता नहीं चला है जिसकी तुलना रामायण में बताई गई संजीवनी से की जा सके। रामायण के अनुसार जब हनुमान संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए तो वे समूचे 'द्रोण पर्वत' को 'लंका' उठा लाए। रामायण के अनुसार संजीवनी बूटी रात्रि में भी चमकती है। लंका के राजवैद्य सुषेण ने हनुमान को बताया कि हिमालय के द्रोण पर्वत पर जीवनदायक जड़ी-बूटी मिलती हैं जिनमें संजीवनी भी शामिल है। उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी मानते हैं कि ये बूटी राज्य के चमोली जिले में स्थित द्रोणगिरी पहाड़ियों में मिलती है। नेगी के अनुसार संजीवनी को तलाश करने वाली परियोजना की शुरुआत 25 करोड़ रुपये से हो सकती है। परियोजना में केंद्र से करीब 150 करोड़ रुपये मदद की जरूरत होगी। नेगी ने कहा, 'जब परियोजना शुरू हो जाएगी तभी सही लागत का अनुमान लग सकेगा।'

नेगी ने बताया कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार को प्रारंभिक प्रस्ताव भेज दिया है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक से चर्चा हो चुकी है। नेगी ने कहा कि केंद्र को शीघ्र ही विस्तृत प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, 'हमने ब्योरा तैयार करने के लिए एक टीम बनाई है।' प्रारंभिक प्रस्ताव में केंद्र से आर्थिक मदद के अलावा संसाधनों (वैज्ञानिक इत्यादि) की भी मदद मांगी गई है। नेगी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने ऋषिकेश में शोध संस्थान बनाने के लिए जमीन भी चिन्हित कर ली है। ये संस्थान संजीवनी बूटी समेत सभी जड़ी-बूटियों पर शोध करेगा। ●

घटती संख्या के बावजूद बढ़ती धमक

2001 में 12.73 करोड़ किसान थे, इनमें से 4.19 करोड़ (33 प्रतिशत) महिलाएं थीं। 2011 में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की संख्या घटकर 3.60 करोड़ (30.3 प्रतिशत) रह गयी, लेकिन इसके बावजूद महिला किसान, पुरुष किसानों को न केवल बराबर की टक्कर दे रही हैं, बल्कि कामयाबी की नई मिशाल भी पेश कर रही हैं।

■ महेन्द्र बोरा/ललित पांडे

ज्यादा तापमान में मशरूम उगाकर बनी 'मशरूम लेडी'

मशरूम लेडी के नाम से मशहूर देहरादून की छोटी कदकाठी की एक लड़की आज बड़े-बड़ों को रोजगार के हुनर सिखा रही है। नाम है दिव्या रावत। मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुकी दिव्या ने 35 से 40 डिग्री तापमान में मशरूम उत्पादन कर इस क्षेत्र में रोजगार की नई संभावनाओं को जन्म दिया है, जबकि आम धारणा यही है कि मशरूम उत्पादन कम तापमान (20 से 22 डिग्री) में ही संभव है। दिव्या का घर न सिर्फ मशरूम की प्रयोगशाला है, बल्कि सीखने वालों के लिए किसी उच्च कोटि के संस्थान से कम नहीं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद करीब तीन वर्ष तक दिल्ली में एक संस्थान से दूसरे संस्थान में नौकरी करने के बाद दिव्या ने अपना काम करने की ठानी। 2013 में शुरू हुआ दिव्या का यह सफर आज सौम्या फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में खड़ा है। एक ऐसी कंपनी जो कई लोगों को रोजगार देने के साथ सालाना लाखों के टर्नओवर तक पहुंच चुकी है।

फौजी अफसर स्व. तेज सिंह रावत की इस बेटी का आज मोथरोवाला क्षेत्र में एक तीन मंजिला मकान है, जिसमें पहली और दूसरी मंजिल में वह अपना मशरूम प्लांट चलाती हैं। इस प्लांट में वर्ष भर में तीन तरह का मशरूम उत्पादित किया जाता है- सर्दियों में बटन, मिड सीजन में ओएस्टर और गर्मियों में मिल्की मशरूम। बटन एक माह, ओएस्टर 15 दिन और मिल्की 45 दिन में तैयार होता है। मशरूम के एक बैग को तैयार करने में 50 से 60 रुपये लागत आती है, जो फसल देने पर अपनी कीमत का दो से तीन गुना मुनाफा देता है। प्रदेश में 2013 की आपदा के बाद दिव्या ने अपने पैतृक गांव कंडारा, चमोली गढ़वाल जाकर महिलाओं को मशरूम का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने की ओर हाथ बढ़ाया। दिव्या ने गांव में खाली पड़े खंडहरों और मकानों में ही मशरूम उत्पादन शुरू किया। इसके अलावा कर्णप्रयाग, चमोली, रुद्रप्रयाग, यमुना घाटी के विभिन्न गांवों की महिलाओं को इस काम से जोड़ा।

80 साल में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन करके रामप्यारी ने पाया पुरस्कार

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की बामनवास तहसील के गोठ गांव की 80 वर्षीय रामप्यारी मीणा को कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'कृषि कर्मण अवार्ड' से पुरस्कृत किया। यह पुरस्कार वर्ष 2014-2015 के दौरान राजस्थान को गेहूं उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया गया है। देशभर में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन का कीर्तिमान बनाते हुए राजस्थान ने 2961 किलो प्रति हेक्टेयर उत्पादन के हिसाब से 33.18 लाख हेक्टेयर भूमि में 98.24 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया, जिसमें 80 साल की उम्र में भी रामप्यारी ने अकेले 59.20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन किया।

पढ़-लिखकर खेतीबाड़ी की बात की तो लोगों ने मजाक बनाया: दिव्या रावत

छोटी उम्र में अपनी लगन और मेहनत से 'मशरूम लेडी' के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी दिव्या का काम उत्तराखंड के गांवों में खंडहर हो चुके मकानों को रौनक और बेरोगजार हाथों को हुनर दिला सकता है, बशर्ते उनसे कुछ सीखने की जरूरत है। दिव्या से 'कृषि चौपाल' की बातचीत के अंश:

● आपके दिमाग में मशरूम की खेती का आइडिया कहां से आया और इसके लिए कहां से प्रशिक्षण लिया?

मैंने उत्तराखंड के लोगों की आजीविका के लिए रोजगार के बारे में रिसर्च किया। यहां पहाड़ में जो खेतीबाड़ी है उसमें कई चुनौतियां हैं। बारिश पर निर्भर खेती है, जमीन कम उपजाऊ है, जंगली जानवरों, बंदरों, सूअरों आदि से खेतीबाड़ी को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे हालातों में मशरूम की खेती यहां बिल्कुल फिट बैठती थी। मशरूम कम लागत में ज्यादा मुनाफा देता है। यह जलवायु आधारित खेती नहीं है बल्कि तापमान आधारित खेती है। इसकी खेती बंद कमरे में होती है इसलिए बाहरी मौसम या जानवरों से कोई खतरा नहीं है। मेहनत भी कम लगती है। बाजार में मांग भी बहुत है। कैश क्रॉप है, यानी पैसा हाथ के हाथ मिलता है। इसके लिए मैंने सबसे पहले उत्तराखंड और उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन (हिमाचल प्रदेश) से विधिवत ट्रेनिंग ली। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बहुत से मशरूम उत्पादकों से उनके अनुभव को समझा। फिर 2013 में अपना काम शुरू कर दिया।

● मशरूम की खेती के लिए देहरादून को चुनने की क्या वजह रही?

मैं उत्तराखंड से हो रहे पलायन को देख रही थी और दुखी भी थी। युवा महज चार-पांच हजार की नौकरी के लिए अपना घरबार और खेतीबाड़ी छोड़कर दिल्ली या दूसरे शहरों में होटल, मॉल और दुकानों में सेल्समैन की नौकरी कर रहे थे। मैं सोसल वर्क से जुड़ी थी। यह समाज सेवा के साथ एक बौद्धिक क्षेत्र है। मैंने सोचा कि मुझे अपना सामाजिक दायित्व अपनी जड़ों पर निभाना चाहिए, वहां कुछ नया करके दिखाना चाहिए। इसलिए मैंने दिल्ली की अच्छी-खासी नौकरी छोड़कर वापस अपनी जड़ों की ओर पलायन किया। उत्तराखंड के जनपद चमोली में अपने पैतृक गांव कोट-कण्डारा में मैं आठ महीने रही और स्थानीय बाजारों चमोली, नंदप्रयाग, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग आदि जगहों पर सफलतापूर्वक मशरूम का बाजार लगाया। वहां के लोगों को मशरूम पैदा करना सिखाया।

● शुरुआत में आपको किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा?

मेरी उम्र मात्र 22-23 साल थी और मैं लड़की थी। जब मैंने खेतीबाड़ी से जुड़ने की बात की तो लोगों को मजाक बनाया। लेकिन मैं कुछ नया सोचकर और दिल्ली छोड़कर आयी थी। मैं चुपचाप अपने काम में लग गयी। दिल्ली में रहते मैंने देखा कि मशरूम बड़ी फैक्टरियों में उगाया जा रहा है। देश के कुछ हिस्सों में किसान मशरूम उगाते तो हैं पर केवल सीजनल। इसका एक कारण मशरूम की खेती की सही जानकारी का अभाव है। इसलिए मुझे खुद ही एक ऐसा मशरूम मॉडल बनाना पड़ा जिसका तामझाम फैक्टरी जैसा न हो और किसान सालभर आसानी से मशरूम उगा सकें और आमदनी कमा सकें।

● आर्थिक संसाधन कहां से जुटाए? क्या सरकार या बैंक से कोई मदद वगैरह ली?

परिवार में भाई-बहनों और मां ने प्रारंभिक मदद की। मैंने पहाड़ (गढ़वाल) में खंडहर पड़े खाली मकानों के अंदर काम शुरू कर दिया। देहरादून में भी खाली मकान का इस्तेमाल किया। बैंकों ने कोई मदद नहीं की और न ही कोई सरकारी मदद मिली।

● खेतीबाड़ी में उत्पादन आसान काम है लेकिन उसकी मार्केटिंग उतनी ही मुश्किल, ये सब आपने कैसे मैनेज किया?

मैंने मशरूम बेचने के लिए खुद जगह-जगह जाकर रोड-शो किये। लोगों और बाजार से पिज्जा वालों की तरह ऑर्डर लिये। लड़कों से मोटरसाइकिल से कस्टमर्स तक डिलीवरी करायी। बड़ी सब्जी मंडी में भी मिल्की मशरूम की नई वैराइटी दी जिसमें हमारी मोनोपॉली है। आज मैं खुद एक ब्रांड की तरह हो गयी हूं। सब प्यार से मुझे 'मशरूम लेडी' कहते हैं।

● आपने अपनी कंपनी में कितने लोगों को रोजगार दिया है और कितनी प्रतिशत महिलाएं आपसे जुड़ी हैं?

मेरी कंपनी में 10-12 लोग नियमित रूप से काम कर रहे हैं। बाकी 10-20 लोग फसल लगाने, अंडों का मिश्रण और फसल कटाई के दौरान काम करते हैं। कंपनी में 80 प्रतिशत महिलाएं और 20 प्रतिशत पुरुष काम करते हैं। लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि अब मेरे बिजनेस मॉडल में युवा दिचस्पी लेने लगे हैं।

● आप कहां तक पढ़ी-लिखी हैं? नौजवान बेरोजगार पीढ़ी से कुछ कहना चाहती हैं?

मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी से सोसल वर्क में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मास्टर डिग्री ली है। बेरोजगार युवा पीढ़ी से यही कहना चाहती हूं कि जहां चाह वहां राह। लगन व मेहनत से किया हर काम रंग लाता है।

● कोई पुरस्कार या सम्मान जो आपको मशरूम की खेती के लिए मिल चुके हैं?

जी हां। मैं उत्तराखंड राज्य बागवानी विभाग द्वारा मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए पूर्व कृषि मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा सम्मानित की जा चुकी हूं। जनपद चमोली के कोट-कण्डारा में प्रशंसनीय मशरूम की खेती हेतु मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा सम्मानित की जा चुकी हूं। उद्यमिता और कृषि के लिए मुझे 'संजीवनी रत्न' पुरस्कार मिल चुका है। जी टीवी के जी जिंदगी द्वारा महिला सशक्तीकरण के लिए पुरस्कृत हो चुकी हूं। इसके अलावा इंडिया इस्लामिक सेंटर दिल्ली में अभिव्यक्ति कार्यशाला में 'आह्वान' संस्था द्वारा मशरूम की खेती से पलायन रोकने के लिए सम्मानित किया जा चुका है। ●

नई तकनीक से बनाई रेखा ने अपनी पहचान

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जलालपुर गांव में रहने वाली महिला किसान रेखा त्यागी ने जीवन में कड़े संघर्षों के बाद सफलता की एक नई इबारत लिखी है। रेखा त्यागी ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जो बड़े-बड़े किसान और जमींदार नहीं कर पाते हैं। रेखा बाजरे की खेती में बम्पर पैदावार करने वाली प्रदेश की पहली महिला किसान बन गई हैं। रेखा के इस संघर्ष और उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनका सम्मान किया। एक आम महिला की तरह रेखा त्यागी का भी जीवन सामान्य तौर पर चल रहा था। रेखा के पति किसानी करते थे और पांचवी तक पढ़ी-लिखी रेखा घर में अपने तीन बच्चों को एक कुशल गृहिणी की तरह संभालती थी। लेकिल दस साल पहले रेखा के पति का देहांत हो गया। पति की मौत के बाद रेखा की जिंदगी बहुत कठिन हो गई थी। उनके सामने घर चलाने के लिए आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। खेत तो थे, लेकिन खेती में लगाने के लिए न तो रेखा के पास पैसे थे और न ही खेती करने और कराने का कोई अनुभव। अपने जेठ और देवरों की आर्थिक मदद से रेखा ने मजदूरों से खेती कराना शुरू किया। ये सिलसिला कई सालों तक यूं ही चलता रहा। रेखा ने खेती में सालों तक नुकसान उठाया। खेती का लागत मूल्य निकालना भी कठिन हो रहा था। हालांकि खेती में नुकसान सिर्फ रेखा की ही कहानी नहीं थी। कभी बारिश तो कभी सूखे से राज्य के किसान बेहाल थे। पिछले चार सालों से सफेद कीटों के आक्रमण के कारण सोयाबीन की फसल भी प्रभावित हुई थी। फसलें बर्बाद होने और कर्ज न चुकाने के कारण प्रदेश में पिछले तीन सालों में ढाई हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में, रेखा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि या तो अपनी कृषि योग्य लगभग 20 हेक्टेयर जमीन को ठेके पर किसी और किसान को दे दे या फिर इस नुकसान के व्यवसाय को लाभ में बदला जाए।

खेती में लगातार होने वाले नुकसान से उबरने के लिए रेखा ने अपने खेतों में नई किस्म की फसल लगाने के बारे में सोचा। जिला कृषि अधिकारियों की सलाह पर रेखा ने अपने खेत में बाजरे की फसल लगाई। बाजरे की फसल लगाने के लिए रेखा ने परंपरागत पद्धति को त्याग कर नई और वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया। नई नस्ल के बीज और मिट्टी की जांच करके खेतों में खाद-पानी दिया गया। खेतों में सीधे तौर पर बाजरा बोने के बजाए पहले बाजरे का छोटा पौधा तैयार किया गया। पौधा तैयार होने के बाद इसे अपनी जगह से उखाड़ कर खेतों में लगाया गया। इस तरह सघनता पद्धति से रोपे गए बाजरे की खेती में रेखा ने रिकार्ड तोड़ उत्पादन हासिल किया। आमतौर पर परंपरगत तकनीक से की गई बाजरे की खेती में प्रति हेक्टेयर 15 से 20 क्विंटल बाजरे का उत्पादन होता है, लेकिन सघनता पद्धति से की गई खेती में रेखा ने एक हेक्टेयर खेत में लगभग 40 क्विंटल बाजरे की पैदावार की। इस तरह रेखा ने बाजरा उत्पादन करने वाले किसानों के साथ-साथ सरकार का भी ध्यान अपनी ओर खींचा

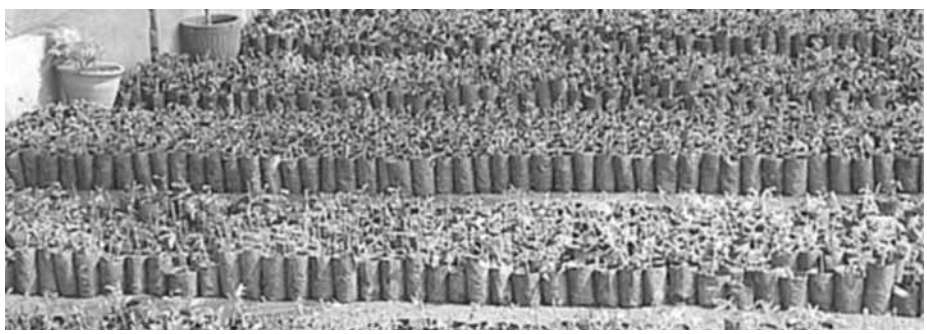

ससुर के ताने भी नहीं रोक पाये संगीता के कदम

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पारू के बंदे गांव की रहने वाली संगीता देवी महिला किसानों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। ससुर के ताने भी संगीता के कदम नहीं रोक पाये और उन्होंने एक साल में नौ हजार पॉपलर पौधों की नर्सरी तैयार कर दी। इस काम के लिए खुद की जमीन कम पड़ गयी तो लीज पर जमीन लेकर उसमें पौधे लगाये। भाई ने हौसला अफजाई करके आगे बढ़ने की सीख दी। दरअसल, संगीता के मायके में चार साल पहले इसकी खेती उनके भाई अखिलेश कुमार ने शुरू की थी। इसे देखने के बाद ही संगीता के मन में यह इच्छा जगी थी। संगीता ने बताया कि पहले तो ससुराल वालों ने इसका विरोध किया। ससुर डॉ. राजेंद्र सिंह पूसा कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह काम तुमसे नहीं होगा। इस ताने को सुनने के बाद उन्होंने यह ठान लिया कि अब हर हाल में वह पॉपलर की खेती करेंगी। इसके बाद पति नरेंद्र ने सहयोग काम करना शुरू किया। संगीता ने बताया कि शुरुआत की परेशानियों ने मेरे कदम रोक से दिये थे, लेकिन भाई के हौसले ने मेरे इरादे को और मजबूत कर दिया। भाई से फॉर्म भरने से लेकर खेती के गुर भी सीखे। विभाग ने 12 हजार पौधे दिये। इनमें करीब नौ हजार पौधे बचे। इन पौधों की कीमत अब प्रति पौधे 15 रुपये हो गई है। जमीन कम पड़ गयी तो गांव में ही जमीन लीज पर ले ली। अब ससुराल के लोग भी पूरी तरह से साथ हैं। परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने में मेरा भी सहयोग हो गया है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है।

सुषमा के अनार देखने दूर से आते हैं किसान

पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर की महिला किसान सुषमा भी उन्हीं चंद नामों में एक हैं, जिन्होंने अपनी जमीन में सहफसली खेती के साथ अनार की लहलाती फसल को खड़ा कर किसानों के सामने नई मिसाल प्रस्तुत की। सुषमा ने अपनी लगन और मेहनत के साथ इस मुहिम को करीब तीन साल पहले शुरू किया और दो एकड़ जमीन में परंपरागत खेती के बजाय अनार के बाग लगाने का एक कठोर फैसला लिया। उत्तर प्रदेश में किसान अभी तक अनार की खेती नहीं करते हैं और उनकी इसमें रुचि भी नहीं होती है। महिला होने के बावजूद सुषमा इस ओर आगे बढ़ीं और आज उनके दो एकड़ में भरपूर अनार के साथ-साथ सहफसली आलू और पपीते की फसल भी लहलहा रही है। इससे वे दोगुना लाभ कमा रही हैं। उन्होंने अपने गांव में गणेश और कांधारी प्रजाति का अनार लगाया है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश में भगवा, रूबी, मृदुला अनार की प्रजातियां पाई जाती हैं।

सुषमा ने बताया कि उन्होंने अपने इस अभियान का नाम थ्री-ए संरक्षण रखकर शुरुआत की थी और अब उन्हें इसमें काफी फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि परंपरागत खेती से प्रति बीघा में किसान केवल 25 हजार रुपये प्रतिवर्ष कमा पाता है, जबकि अनार से आय को 50 हजार रुपये तक पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ-साथ अनार के बाग में आलू, पपीते की अतिरिक्त फसलों को लगाकर किसान अलग से भी लाभ ले सकते हैं। आज महिला किसान सुषमा के नये प्रयोग के बाद उसकी सफलता देखने के लिए उसके गांव में दूर-दूर से किसान आ रहे हैं।

छह हजार रुपये से आठ गुनी आय

मुंबई में पिछले साल मार्च में सिंधुदुर्ग स्थित वाडाटर क्रीक में दस महिलाओं ने तीन दिनों तक पुराने ऑइस्टर (सीप) के खोल के साथ बांस का खांचा खड़ा किया। पंद्रह महीने बाद उन महिलाओं ने छह हजार रुपये की लागत से ऑइस्टर से 125 किलो मांस निकाल कर पचास हजार रुपये कमाए। ये महिलाएं राज्य में ऑइस्टर फार्मिंग करने वाली पहली किसान हैं। इन महिलाओं में से 40 वर्षीया कस्तूरी धोके कहती हैं कि अब हमें क्रीक के दलदली इलाकों में जाने और भाग्य के भरोसे ऑइस्टर खोजने की जरूरत नहीं है। अब हम ऑइस्टर पालन कर सकते हैं और कम प्रयास में ठीक-ठाक कमा भी सकते हैं। हम लोग इसको अपने गांव में भी फैलाना चाहते हैं और गांव के अन्य लोगों तक खबर भी भिजवा चुके हैं। मार्च 2014 में बांस और अन्य तरह की मजदूरी के खर्च के लिए छह हजार रुपये की आरंभिक लागत से शुरू की गई इस परियोजना में आठ गुनी आय हुई।

करमवीर और रिप्पी की खेती से चौंक उठा गांव

राजस्थान के कोटा की रिप्पी और करमवीर अपनी जमीन को ट्रैक्टर से जोतती हैं। अनाज बेचने मंडी भी खुद जाती हैं। दरअसल पिता की मौत के बाद उनकी 80 बीघा जमीन पर काम करने वाला कोई नहीं था। परिस्थितियों को ध्यान में रखकर 30 वर्षीय करमवीर और 24 वर्षीय रिप्पी ने जब अपने खेतों पर काम करना शुरू किया, तो पूरा का पूरा गांव चौंक उठा। अक्सर बाजार में रात भर अनाज की रखवाली करते समय शराबियों से पाला पड़ता, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दोनों बहनों ने दरखास्त दी, प्रशासन और मंडी के साथ संघर्ष किया और अपने लिए एक अच्छा व्यवसाय चुना, जिसके बाद दोनों ने फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा।

डीएम ने बनाया निरूपा को ब्रांड एंबेसडर

अमूमन पति की मौत के बाद महिलाएं टूट जाती हैं, लेकिन कई साहसी महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर की चौखट लांघ कर कुछ कर गुजर जाती हैं। नालंदा के सारिलचक गांव की निरूपा देवी एक ऐसी ही महिला हैं, जो पति की असामयिक मौत के बाद नहीं टूटी और आज मशरूम उत्पादन में उपलब्धि हासिल कर अपनी खास पहचान बना चुकी हैं। निरूपा की लोकप्रियता से प्रभावित तत्कालीन डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने इन्हें लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ब्रांड एंबेसडर भी बनाया था। आज से करीब चार साल पहले तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी सुदामा महतो सारिलचक गांव के किसानों को श्रीविधि तकनीक से अवगत कराने पहुंचे थे। इसी दरम्यान उनकी नजर घर की चौखट पर बैठी गुमसुम निरूपा देवी पर गई तो पूछताछ में उसने कुछ स्वरोजगार कर स्वावलंबी बनाने की इच्छा जाहिर की। तब डीएओ महतो ने निरूपा को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लेने और इसकी खेती करने की सलाह दी। निरूपा बताती हैं कि किसी भी रोजगार में सफल होने के लिए पहले उसकी बारीकियों और इससे संबंधित प्रशिक्षण लेना जरूरी है। साथ ही लक्ष्य पर पूरा ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। निरूपा खुद द्वारा उत्पादित मशरूम, मशरूम आचार, ड्राई मशरूम एवं मशरूम हार्लिक्स का स्टॉल कई मेलों में लगा चुकी हैं। वह बताती हैं कि इन स्टॉलों पर मशरूम की खूब डिमांड होती है। इससे उसे प्रशंसा के साथ अच्छा मुनाफा भी मिलता है।

सबके लिए आकर्षण का केन्द्र बने रीना के खेत

राजस्थान के भीलवाड़ा में उच्च शिक्षा में अग्रणी रहने के बावजूद बड़ी नौकरी का मोह छोड़कर खेती-किसानी को अपनाने वाली रीना तंवर के खूब चर्चे हैं। रीना के खेत सबके लिए आकर्षण का केन्द्र बने हुए है। रीना ने एक साल पहले सरकार की मदद से पॉली हाउस के माध्यम से खेती-किसानी का काम शुरू किया था।

उन्होंने करीब एक बीघा में डेढ़ लाख रुपए से अधिक का खीरा हर माह उपजाकर एक नई मिशाल पेश की। भीलवाड़ा से करीब 10 किलोमीटर दूर रीना तंवर के खेत में दो पॉलीहाउस खड़े हैं। आधुनिक तकनीक से तालमेल बिठाकर खेती-किसानी के क्षेत्र में भाग्य आजमाने वाली ये महिला किसान आज समाज के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन गयी है। रीना का कहना है कि उन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक तकनीक के साथ खेती करने का मन बनाया। इसके लिए उन्होंने अपने पति महेन्द्र सिंह तंवर को राजी किया।

इसके बाद सरकार की मदद से बंजर जमीन पर पॉलीहाऊस लगाया। इसमें फसल आने तक हमारे कुल छह लाख रुपये खर्च हुए, जबकि आमदनी करीब 16 लाख रुपये तक की हुई। तंवर का कहना है कि महिलाओं के लिए खेती में कई रास्ते खुले हुए हैं।

बाल-वधू जया देवी बन गयी 'ग्रीन लेडी'

महज बारह साल की आयु में जया देवी का विवाह हो गया और सोलह साल की आयु में वह एक बेटी की मां बन गई। कई अन्य की तरह वे बिहार की एक बाल-वधू बन कर ही रह सकती थीं, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जिस पर चल कर वह बिहार की 'ग्रीन लेडी' बन गई। एक नर्स ने उन्हें एक समूह बनाने का सुझाव दिया, फिर उन्होंने साल 1997 में अपने गांव सारधी में हाशिए पर छूट गए समुदायों खासतौर से महिलाओं की मदद की और उन्हें महाजनों के चंगुल से निकालकर वित्तीय स्तर पर स्वतंत्र बनाया।

जया बताती हैं कि गांव के साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी वह यह कि यहां आय का कोई साधन नहीं था। फसल पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर थी जो कि हमेशा असमान होती थी। इसलिए हमने वर्षा जल के संचयन की शुरुआत की। जया ने ग्रामीणों को एकजुट कर वर्षा जल इकठ्ठा करने के लिए एक तालाब बनाया। उन्होंने समझा-बुझाकर इस काम के लिए गांव वालों को श्रमदान के लिए तैयार किया और सबने मिल-जुलकर एक तालाब का निर्माण किया। उनके प्रयास धीरे-धीरे परिणाम की ओर बढ़ने लगे। तालाब की मदद से अच्छी तरह सिंचित खेतों ने अगले मौसम में बंपर फसल का उत्पादन किया, जिससे किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा और प्रोत्साहित होकर उन्होंने एक प्रस्ताव नाबार्ड के समक्ष रखा। उनके प्रयासों से प्रभावित नाबार्ड उनके समर्थन में आगे आया और गांव में छह और तालाब बनवाने में उनकी मदद की।

राजकुमारी देवी बन गई 'किसान चाची'

बिहार के मुजफ्फरपुर की 60 साल की राजकुमारी देवी पूरे बिहार में 'किसान चाची' के तौर पर मशहूर हैं। 1996 में उन्होंने अपने ढाई बीघे खेत में सब्जी और फलों की खेती शुरू की। खेती-किसानी से जुड़े लघु उद्योगों को उन्होंने महिला सशक्तीकरण का जरिया बनाया। 30 किलोमीटर के दायरे में महिलाओं को खेती-किसानी के गुर बताने के लिए राजकुमारी देवी साइकिल से चलती हैं। 300 से ज्यादा महिलाओं को प्रेरित करके राजकुमारी देवी ने स्वयंसेवी समूह बनाया है। यह समूह तरह-तरह के अचार तैयार करता है और 10 क्विंटल अचार सालाना देशभर के मेलों में बेचता है। 2007 में राजकुमारी देवी को बिहार सरकार ने 'किसान श्री' से सम्मानित किया।

खेती करने लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर जा पहुंची शोभा

खेती से उनकी अभी बहुत ज्यादा आय तो नहीं हो रही है, लेकिन खेती के प्रति उनके जनून को हर कोई सलाम करता है। शोभा रानी एक कारोबारी परिवार से हैं और उनकी पूरी फैमिली लखनऊ में रहती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर बाराबंकी जिले के सैदापुर में अपने गांव जाकर खेती करने का फैसला किया। उनके इस फैसले का घर में काफी विरोध हुआ, लेकिन वे टस से मस नहीं हुई। उनके बेटे ने जरूर उनकी हौसला अफजाई की और आज जब उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया तो पूरा परिवार उनके हौसले को सलाम कर रहा है। शुरुआत में वे इजराइली तकनीक से पॉलीहाउस में शिमला मिर्च उगा रही थीं। अब फूलों सहित कई चीजों में हाथ आजमा रही हैं। ●

पंचायतों की 'चैम्पियन' महिलाएं

राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में विभिन्न महिलाओं से की गई बातचीत से निष्कर्ष निकलता है कि अब हालात बदल रहे हैं। जिस घर में शौचालय बनता है उसका इस्तेमाल हो इसकी जिम्मेदारी भी पंचायतें निभा रही हैं। स्वच्छता की आदत बनाने में और लोगों की पुरानी सोच को बदलने के लिये अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं।

चांदनी

■ अन्नू आनंद

राजस्थान के ब्लॉक आमेर में गांव नांगल सुसावतान पंचायत की युवा सरपंच चांदनी तेज-तेज कदमों से गांव के हर घर में घुसती और वहां बने शौचालय का दरवाजा खोलकर हमें दिखाती। गांव के कच्चे-पक्के सभी घरों में शौचालय बने हुए थे। चांदनी पिछले दो महीनों से इसी काम में लगी है।

22 साल की चांदनी बीएड परीक्षा की तैयारी कर रही है। लेकिन उसे गांवों के लोगों को खुले में शौच से मुक्त कराने की चुनौती की अधिक चिन्ता है। वह बताती है कि काम सरल नहीं था। बहुत से लोगों के घर पहले से शौचालय बने थे लेकिन उनके नाम सूची में थे। इन नामों को सूची से निकालना फिर नए नामों को शामिल करना, परिवारों को शौचालय निर्माण के लिये सरकार द्वारा 15 हजार रुपए का खर्च दिये जाने की जानकारी देना, फिर राशि को उनके अकाउंट में डलवाना। ये सभी प्रक्रिया पूरी करने में काफी भागदौड़ करनी पड़ी।

लेकिन वह मानती हैं कि जो मुश्किलें गांव की महिलाओं और

वनिता राजावत

लड़कियों को शौचालय न होने के कारण आ रही थीं उसके सामने ये काम कठिन न था। आज चांदनी की पंचायत के पांचों गांवों के 1632 घरों में शौचालय बन चुके हैं। निरीक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है लेकिन अभी प्रमाण पत्र मिलना बाकी है।

यहां के दौलतपुरा पंचायत की सरपंच वनिता राजावत पिछले साल दूसरी बार सामान्य सीट से चुनाव जीत कर सरपंच नियुक्त हुई हैं। आंगनवाड़ी वर्कर रह चुकी वनिता साफ-सफाई के बारे में बेहद जागरूक हैं। वह साफ कहती हैं, 'हम महिलाएं घर में गंदगी सहन नहीं कर पातीं। पंचायतों का प्रतिनिधित्व करने से गांव भी हमारे घर-परिवार बन जाते हैं। गांव में गंदगी फैले और घर-परिवार की लड़कियां अपनी निजी सफाई और शौच की जरूरतों को पूरा न कर सकें तो हमारा सरपंची करने का क्या फायदा?' इसलिये उसकी प्राथमिकता फिलहाल पंचायत के तीनों गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। वनिता का मानना है कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत से उन्हें शौचालयों की जरूरत को पूरा करने की ताकत मिली है। 45 वर्षीय बी. कॉम पास वनिता अब जी-जान से इसी काम में जुटी हैं।

सरपंच वनिता बताती हैं कि कुछ समय पहले उसके गांव के कुछ घरों की महिलाएं उसके पास आईं और उन्होंने बताया कि उनके घर में पांच से सात छोटे-छोटे बच्चे हैं। जिन्हें पांच बजे से पहले उठाकर शौच के लिये बाहर भेजना पड़ता है। वनिता के मुताबिक गांव में अब खुली जगह नहीं बची। चारों तरफ मकान बन जाने के कारण उन्हें और उनके बच्चों को हाईवे पर जाना पड़ता था। वहां बैठने पर उन्हें लोगों से पिटने और यातना का डर सताता था। परेशान होकर वे शौचालय बनाने के लिये उससे मदद मांगने आये।

राजस्थान के खोरा मीना पंचायत की सरपंच 23 वर्षीया सीमा एम कॉम की पढ़ाई कर रही है उसकी सात महीने की बच्ची है। लेकिन घर, पढ़ाई और पंचायत के तीनों मोर्चों को वह बेहद ही कुशलता से सम्भाल रही हैं। उसका मकसद यही है कि गांव की कोई भी लड़की अशिक्षित न रहे और कोई लड़की या महिला बीमारी या हिंसा से न मरे। इसके लिये वे सबसे पहले गांव को खुले में शौच से मुक्त कराना चाहती है।

सरपंच सीमा के मुताबिक, 'गांवों में भी माहौल अब कोई अच्छा नहीं रहा। इसलिये लड़कियां अक्सर सुबह या रात को अकेले में बाहर जाने में डरती हैं। बढ़ती अपराध की घटनाओं के डर से उन्हें परिवार के किसी बड़े को साथ ले जाना पड़ता है। जो हर समय सम्भव नहीं हो पाता।'

सरपंच सीमा के मुताबिक गांवों में पहले भी बहुत से घरों में शौचालय थे लेकिन घर के लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इसके लिये सीमा ने स्कूलों में जाकर लड़कियों के साथ मीटिंग की और उन्हें शौच के लिये बाहर जाने की तकलीफों के बारे में समझाया। सीमा बताती है, 'मैंने लड़कियों को कहा कि वे अपने परिवार के लोगों को घर में शौचालय बनाने और उसका इस्तेमाल करने की जिद करें।'

सीमा के मुताबिक गांवों के कुछ बुजुर्ग खुले में जाने की पुरानी आदत के कारण शौचालय बनाने में रुचि नहीं दिखाते। लेकिन अब गांवों की लड़कियां स्कूलों में जाने लगी हैं। खुले में

सीमा

पिछले दो दशकों से अधिक समय से पंचायतों में चुनकर आने वाली इन महिलाओं की भूमिका अब बदल चुकी है। उनके काम काज का स्त्री पक्ष अब दिखाई देने लगा है यानी वे अपने और अपनी महिला साथियों के साथ होने वाले अन्याय को समझने लगी हैं। शासन चलाने के ककहरे को सीखने के बाद अब वे खुद को सत्ता से बाहर रखने की साजिशों को समझने लगी हैं।

शौच जाने वाली लड़कियों के साथ हिंसा की घटनाओं के प्रचार के कारण भी वे अब शौच के लिये बाहर जाने से डरती भी हैं। इसके अलावा वे अब इसे शर्म और आत्मसम्मान का मसला भी मानती हैं इसलिये हमारे थोड़े से प्रोत्साहन से वे परिवार वालों को समझाने में सफल हो रही हैं।

सीमा की तरह अन्य महिलाओं ने भी बताया कि घर की लड़कियां जब चाहे तब शौच के लिये बाहर नहीं निकल पातीं। ऐसी परिस्थितियों में अक्सर लड़कियां पेशाब या शौच जाने की समय असमय जरूरत को पूरा करने में असमर्थ रहती हैं। जिससे उन्हें कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बना रहता है।

महिलाओं को अक्सर घर या घर के नजदीक या काम पर जन-सुविधाओं के अभाव में मूत्र को रोकना पड़ता है। मूत्र रोकने से ब्लैडर में दबाव बढ़ता है जिससे मूत्राशय का स्तर बढ़कर कभी-कभी किडनी तक पहुंच जाता है। जिससे वे वल्वोवोवे जिनाइटिस जैसी बीमारियों का शिकार होती हैं। इसके अतिरिक्त खुले में शौच जाने वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद कई प्रकार के इन्फेक्शन होने की सम्भावना अधिक रहती है।

जयपुर स्थित इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के प्रोफेसर और जन स्वास्थ्य अभियान के प्रशिक्षक श्री सुनीत कुमार अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में बच्चों और महिलाओं की मौतों का अधिक कारण स्वच्छता का अभाव होता है। इन्फेक्शन के कारण गांवों में नवजात शिशु मृत्य दर प्राय: अधिक होती है। गर्भावस्था या प्रसव के समय साफ-सफाई और स्वच्छता न होने के कारण इन्फेक्शन होने की सम्भावना अधिक होती है। जो महिलाओं की मौत का बड़ा कारण है। उनका कहना था कि खुले में शौच पर रोक लगाना महिलाओं के जीवन को बचाने के लिये जरूरी है। ●

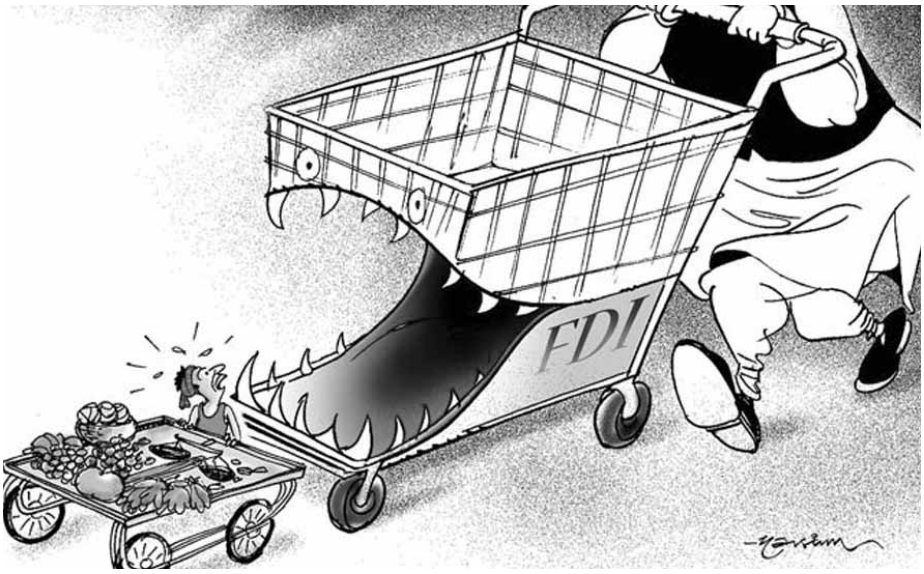

हर सवाल का जवाब नहीं है एफडीआई

पांच दिसंबर 2012 के एक ट्वीट में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था, 'कांग्रेस विदेशियों के हाथों राष्ट्र को सौंप रही है। ज्यादातर राजनीतिक दल एफडीआई के विरोध में हैं, लेकिन अपने ऊपर सीबीआई की तलवार लटकती देख कुछ दलों ने वोट नहीं किया और कांग्रेस पिछले दरवाजे से जीत गई।' जबकि विपक्ष में रहते हुए अरुण जेटली ने 2013 में कहा, 'एफडीआई उपभोक्ताओं, किसानों, व्यापारियों, निर्माताओं और देश के हित में नहीं है। इसी वजह से हम इसका विरोध करते हैं और अंतिम सांस तक हम विरोध करते रहेंगे। हम इस देश के लोगों और व्यापारियों के साथ एकजुट खड़े हैं।' आखिर पिछले चार वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि राजग को अपने पुराने इरादे से पीछे हटना पड़ा?

■ देविंदर शर्मा

भारत में पूंजी प्रवाह के सभी दरवाजों को खोल दिया गया है। व्यापक सुधारों के दूसरे चरण के तहत भारत ने उड्डयन, रक्षा, फार्मास्यूटिकल, एकल ब्रांड खुदरा और खाद्य प्रसंस्करण के अलवा पशुपालन और मधुमक्खी पालन के लिए एफडीआई के लिए दरवाजा खोल दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि एक क्रांतिकारी उदार एफडीआई व्यवस्था भारत को दुनिया में सर्वाधिक मुक्त अर्थव्यवस्था में बदल देगी, जो नौकरी एवं रोजगार सृजन को व्यापक प्रोत्साहन देगा।

चाहे पानी हो या अर्थव्यवस्था, दरवाजों के खुलने से भारी उछाल आता है। लेकिन बांध के दरवाजों (जहां बाढ़ का पानी पीछे नहीं लौटता) के खोले जाने के विपरीत एफडीआई के निर्बाध प्रवाह का मतलब यह नहीं होता कि यह केवल विदेशी पूंजी की बाढ़ लाएगा, बल्कि देश में निवेश किए गए हर डॉलर के बदले दो डॉलर की वापसी भी है।

इसके अलावा, ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में रोजगार विहीन विकास का दौर है, मैं नहीं जानता कि सरकार किस भरोसे पर कह रही है कि देश में एफडीआई के प्रवाह से रोजगार का सृजन होगा।

रोजगार सृजन के संदर्भ में हताशा स्पष्ट दिख रही है। श्रम ब्यूरो के मुताबिक, वर्ष 2015 में मात्र 1.35 लाख रोजगार सृजित किए गए, जो पिछले छह वर्षों में सबसे न्यूनतम है। ऐसे देश में, जहां हर वर्ष 1.25 करोड़ लोग रोजगार पाने की कतार में खड़े हो जाते हैं, वहां मात्र 1.35 लाख लोगों को रोजगार मिलना स्पष्ट दर्शाता है कि हमारा आर्थिक तंत्र रोजगार देने में अक्षम साबित हो रहा है।

खैर, एक वर्ष के आंकड़े के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता, लेकिन पिछले 12 वर्षों (वर्ष 2004 की शुरुआत से, जब डॉ. मनमोहन सिंह ने सत्ता संभाली थी) का रोजगार का ग्राफ उतना ही अंधकारमय बना हुआ है। पिछले 12 वर्षों में मात्र 1.6 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ, जबकि 14.5 करोड़ लोगों को रोजगार की तलाश थी।

इसलिए रोजगार सृजन का दबाव स्पष्ट है। यही वह चीज है, जिसका हल तलाशने की कोशिश मनमोहन सिंह सरकार ने की थी, जब उसने और एफडीआई का रास्ता खोलने का प्रयास किया था। पांच दिसंबर 2012 के एक ट्वीट में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था, 'कांग्रेस विदेशियों के हाथों राष्ट्र को सौंप रही है। ज्यादातर राजनीतिक दल एफडीआई के विरोध में हैं, लेकिन अपने ऊपर सीबीआई की तलवार लटकती देख कुछ दलों ने वोट नहीं किया और कांग्रेस पिछले दरवाजे से जीत गई।' जबकि विपक्ष में रहते हुए अरुण जेटली ने 2013 में कहा, 'एफडीआई उपभोक्ताओं, किसानों, व्यापारियों, निर्माताओं और देश के हित में नहीं है। इसी वजह से हम इसका विरोध करते हैं और अंतिम सांस तक हम विरोध करते रहेंगे। हम इस देश के लोगों और व्यापारियों के साथ एकजुट खड़े हैं।' आखिर पिछले चार वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि राजग को अपने पुराने इरादे से पीछे हटना पड़ा? एफडीआई पर यू-टर्न बिल्कुल राजनीति है।

वर्ष 2015-16 में भारत में 55.46 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया, जो अब तक का उच्चतम रिकॉर्ड है। हालांकि वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि नीति में इस तरह से सुधार किया गया है कि इससे घरेलू रोजगार को नुकसान न पहुंचे, लेकिन राष्ट्रव्यापी चर्चा के बिना अचानक भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलना कई सवाल उठाता है।

उदाहरण के लिए, मधुमक्खी पालन में आखिर क्या समस्या थी कि एपीकल्चर में एफडीआई की अनुमति दी गई। मधुमक्खी पालन किसानों के लिए आय का एक पूरक साधन है, जो पहले से ही गंभीर संकट में हैं। अगर

बड़े विदेशी व्यवसायियों के हित में बाजार पर नियंत्रण की कोशिश की गई, तो ये छोटे किसान इससे भी बाहर हो जाएंगे।

पश्चिमी देशों से उन्नत तकनीक आने के साथ घरेलू उद्योग का मानना है कि यह दुधारु पशुओं की नस्ल भी लाएगा और विदेशी अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा निवेश में बढ़ोतरी होगी। वास्तव में यह देसी नस्लों को बढ़ावा देने की राजग सरकार की नीति के खिलाफ है।

जिस बात की अनदेखी की जा रही है, वह यह कि भारत को नए विदेशी नस्लों की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे अपने देसी नस्ल को वापस लाने की जरूरत है, जो ब्राजील में बढ़िया उत्पादन कर रहे हैं। वर्षों से ब्राजील भारतीय नस्लों की गायों का बड़ा निर्यातक बन गया है। एक खालिस गीर गाय प्रतिदिन 73 लीटर दूध देती है।

यह विवाद तब और बढ़ेगा, जब बड़े बहुराष्ट्रीय डेयरी निगम डेयरी उद्योग के संचालन के लिए अपने पशुपालन केंद्रों की स्थापना करेंगे। भारत में दुग्ध सहकारी संस्थाएं आठ करोड़ दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक मदद करती हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। इन लघु दुग्ध उत्पादकों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।

शुरू में एफडीआई को देश में उच्चतम तकनीक लाने के लिए उचित ठहराया गया था। हालांकि रक्षा एवं उड्डयन के क्षेत्र में सौ फीसदी एफडीआई का रास्ता सरकारी मंजूरी के तहत खोला गया है, लेकिन यह अब स्पष्ट है कि निवेशक देश में उच्चतम तकनीक लाने का इरादा नहीं रखते हैं।

इसी तरह एकल ब्रांड खुदरा के क्षेत्र में सरकार ने व्यावहारिक रूप से उस प्रावधान को हटा दिया है, जो तीस फीसदी स्थानीय स्रोत को सुनिश्चित करता है। एफडीआई का प्राथमिक लक्ष्य नई तकनीक प्रदान करना और घरेलू विनिर्माताओं को विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर लाभ हासिल करने में सक्षम बनाना था।

घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को दरकिनार कर निश्चित रूप से रोजगार सृजन नहीं होगा। दवा क्षेत्र के भी इससे सर्वाधिक प्रभावित होने की आशंका है। भारत को अब तक दुनिया में सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता रहा है।

ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड, दोनों परियोजनाओं में एफडीआई को मंजूरी देने से घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंच सकता है। इससे औसत उपभोक्ताओं को जहां महंगाई का सामना करना पड़ेगा, वहीं स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर भी असर पड़ेगा और रोजगार सृजन की संभावनाएं भी सीमित हो जाएंगी। ●

नहीं रहे वृक्ष मित्र राठौर

मशहूर पर्यावरणविद और एक करोड़ पौधे लगाने के लिए वर्ष 2000 में 'इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार' से नवाजे गये कुंवर दामोदर सिंह राठौर का निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पौधे लगाने में खपा दी। राठौर ने अपने जीवन करीब 160 प्रजाति के आठ करोड़ पौधे लगाए थे। उनके अंतिम वक्त भी उनके सिर के पास पौधे ही रखे थे। 25 मई को पिथौरागढ़ में जंगलों में लगी आग बुझाने के दौरान उन्हें सांस की दिक्कत हुई। अपने अंतिम दिनों में भी उन्होंने पौधों का साथ नहीं छोड़ा और अपनी नर्सरी से कुछ पौधे अस्पताल के कमरे में ले आए। उनका कहना था कि जंगलों को आग से बुझाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर काम करने की जरूरत है। वह मार्मिक अंदाज में कहते थे कि जंगलों को बचाएंगे तभी हम और आप बचेंगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक, अंतिम सांस लेने से तीन दिन पहले बेहद कमजोर होने के बावजूद भी वह कुछ स्कूली बच्चों से मिले और उन्हें करीब 4000 पौधे बांटे। दामोदर ने पेड़ लगाने के अपने इस अभियान की शुरुआत 1960 में की थी। तब से लेकर अब तक उन्होंने 160 से भी ज्यादा प्रजातियों के 8 करोड़ से भी ज्यादा पौधे लगाए थे। उन दिनों कंधे पर बैग टांगे लंबी कदकाठी के दामोदर भनौरा और उसके आसपास के इलाकों में लोगों के लिए बेहद खास चेहरा बन गए। भनौरा में इन दिनों ज्यादातर हिस्सों में हरियाली है और इसका श्रेय दामोदर जी को जाता है।

पथरी में रामबाण औषधि है पत्थरचट्टा

पथरी बहुत कष्टदायी बीमारी है। लोग इससे निजात पाने के लिए सर्जरी करवाते हैं। लेकिन कई तरीके ऐसे भी हैं जिनमें बिना सर्जरी के भी पथरी को आसानी से शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। पत्थरचट्टा भी उन तरीकों में से एक है। आयुर्वेद में पत्थरचट्टे के पौधे को किडनी स्टोन और प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़े रोगों के इलाज में उपयोगी माना गया है। इसे पर्णबीज भी कहते हैं। इसके पत्ते को मिट्टी में गाड़ देने से यह उस स्थान पर उग जाता है। तासीर में सामान्य होने की वजह से इसका प्रयोग किसी भी मौसम में कर सकते हैं। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है।

पत्थरचट्टा के प्रयोग से पथरी आसानी से शरीर से बाहर आ जाती है। इसके सेवन से 10-15 एमएम तक की पथरी पेशाब के जरिये बाहर निकल जाती है। महिलाओं में श्वेत प्रदर, पेशाब में जलन व पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या में भी यह बहुत लाभकारी है।

कैसे करें प्रयोग: पत्थरचट्टा के 4-5 पत्तों को एक गिलास पानी में पीसकर सुबह-शाम जूस के रूप में लगभग 1-2 माह तक पियें। जूस के अलावा पत्तों को चबाकर व पकौड़े बनाकर भी खाया जा सकता है।

ध्यान देने वाली बातें: इस दौरान तंबाकू, चूने, सुपारी आदि का सेवन न करें। जिनको बार-बार पथरी होती रहती है वे हर दूसरे दिन पत्थरचट्टा का आधा पत्ता सेवन करें, लेकिन अस्वास्थ्यकर व्यसनों के साथ-साथ टमाटर के बीजों का सेवन भी न करें। ●

झाबुआ में आशा के बीज

कुछ साल पहले तक इस इलाके में देसी गेहूं बोया जाता था और वह भी बिना रासायनिक खाद और बिना सिंचाई के। भील, भिलाला, पटलिया आदिवासी यहां के बाशिन्दे हैं। देसी बाजरा, डांगर, देसी मक्का, अरहर, ज्वार, भादली, मूंग, उड़द, कुलथी, सांवा, भादी, तिल, चौला, बावटा, राला आदि कई प्रकार के देसी बीज थे। लेकिन अब कई हाइब्रिड आ गए हैं। बीटी कपास आ गया है। ऐसे में कुछ लोग बीज बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनमें संपर्क संस्था भी एक है।

■ **बाबा मायाराम**

झाबुआ का एक गांव है डाबड़ी। वैसे तो यह सामान्य गांव है लेकिन यहां एक किसान के खेत में देसी गेहूं की 16 किस्में होने के कारण यह खास बन गया है। और वह भी बिना रासायनिक खाद और बिना कीटनाशकों के। पूरी तरह जैविक तरीके से देसी गेहूं का यह प्रयोग आकर्षण का केन्द्र बन गया है।

मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावद विकासखंड का गांव है डाबड़ी। मैं यहां पिछले 16 मार्च को गया था। दोपहर का समय था। हल्की हवा चल रही थी। रामलाल पाटीदार अपने खेत में से नमूने के लिये गेहूं की पकी बालें एकत्र कर रहे थे। अलग-अलग किस्मों में क्या अन्तर है, इसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिये।

कुछ साल पहले तक इस इलाके में देसी गेहूं बोया जाता था और वह भी बिना रासायनिक खाद और बिना सिंचाई के। भील, भिलाला, पटलिया आदिवासी यहां के बाशिन्दे हैं। देसी बाजरा, डांगर, देसी मक्का, अरहर, ज्वार, भादली, मूंग, उड़द, कुलथी, सांवा, भादी, तिल, चौला, बावटा, राला आदि कई प्रकार के देसी बीज थे। लेकिन अब कई हाइब्रिड आ गये हैं। बीटी कपास आ गया है। ऐसे में कुछ लोग बीज बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनमें संपर्क संस्था भी एक है।

मैंने खेत के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक घूमकर गेहूं की किस्मों पर नजर डाली। शरबती, ग्वाला, कठिया, वांझिया, बंसी, काली बालीवाला, दाबती, पिस्सी आदि गेहूं किस्में छोटी-छोटी क्यारियों में लहलहा रही हैं। खेत में पेड़ों की बागड़ लगी है, जिससे खेत में नमी व पत्तों की जैव खाद बनती है। कोई गेहूं का पौधा हरा है, कोई पीला पड़ पकने को तैयार है। किसी बाल के दाने भरे हैं, किसी के दाने पोचे। किसी बाल का रंग काला है, किसी का लाल। किस्मों की यही विविधता मोह रही है। सिर्फ इनके रंगों में ही फर्क नहीं है बल्कि यह स्वाद में भी बेजोड़ हैं।

हम अब पेड़ की छांव में बैठकर रामलाल जी से बातें करने लगे। वे बताने लगे कि हमने इन गेहूं की किस्मों को अलग-अलग जगह से एकत्र किया और फिर अपने खेत में अध्ययन के लिये बोया है। ये वे किस्में हैं जो लगभग लुप्त होने के कगार पर हैं, या लुप्त हो चुकी हैं।

वे बताते हैं कि ग्वाला और काली बालीवाला अच्छी उपज देता है और इसके कड़क दाने होते हैं। इसी प्रकार पिस्सी, वांझिया और कठिया कम पानी में हो जाते हैं। वांझिया, शरबती और बंशी में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं।

इन किस्मों में वे जैविक खाद, जैविक नत्रजन व जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल

कर रहे हैं, जो वे खुद तैयार करते हैं। गोबर, तालाब की मिट्टी, राख, आटा, गुड़ और गोमूत्र को सड़ाकर जैविक खाद बनाई जाती है। इसी प्रकार जैविक नत्रजन गोमूत्र, गुड़, छाछ, बेसन और पानी से तैयार की जाती है। इसी प्रकार जैविक कीटनाशक बनाया जाता है। इन सबका समय-समय पर छिड़काव किया जाता है। रामलाल के गेहूं की खुशबू फैलने लगी है। हाल ही में इन किस्मों को देखने के लिये बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए। इस किसान सम्मेलन को संपर्क संस्था ने आयोजित किया था। इस सम्मेलन में सतना जिले के देसी बीजों के जानकार व किसान बाबूलाल दाहिया आये थे। दाहिया जी ने खुद भी देसी गेहूं की 13 किस्में अपने खेत में लगाई हैं।

दाहिया जी ने देसी गेहूं की खासियत बताते हुए कहा कि यहां पहले जो भी फसलें होती थीं वे वर्षा आधारित थीं। गेहूं भी बिना सिंचाई के ही होता था। इसलिये यहां के गेहूं का तना लम्बा होता था जिसमें पानी संचय हो जाता था और उस पानी से फसल पक जाती थी। अनुकूलन की यह क्षमता बरसों में पाई होगी।

वे बताते हैं कि बघेलखण्ड के देसी गेहूं कठिया और कठवी किस्म के होते थे। दोनों के आकार एक जैसे होते थे लेकिन रंग में फर्क होता था। कठिया सफेद होता था और कठवी का रंग लाल। देसी शरबती बोया जाता था, उसका तना भी लम्बा होता था। खाने में स्वादिष्ट होता था। पिस्सी में दाने विरल होते थे और वह भी अन्य देसी किस्मों के समान गुण सम्पन्न थी।

दाहिया जी बताते हैं देसी बीज स्थानीय मिट्टी-पानी के अनुकूल होते हैं। इनमें सभी तरह की परिस्थितियों में उपज देने के गुण मौजूद होते हैं। बारिश की नमी में गेहूं बोया जाता था और अगर एक-दो मावठा मिल जाये तो गेहूं अच्छा पक जाता था।

अल्बर्ट होवार्ड और उनकी पत्नी जी.एल. सी. होवार्ड और हबीबुर रहमान ने ब्रिटिश काल में भारतीय गेहूं पर बरसों अनुसंधान किया था। होवार्ड दंपति ने स्थानीय किस्मों के चयन के जरिए कई किस्में विकसित की थीं जो उपज में वृद्धि और क्वालिटी के लिहाज से बेहतरीन थीं। जिसमें पूसा-4 और पूसा-12 काफी लोकप्रिय हुई थी। पूसा-4 को देसी गेहूं की मुंडिया किस्म से तैयार किया गया था।

गेहूं हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। इसे अनाजों का राजा कहा जाता है। इसमें किसी भी अन्य अनाज से पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। इसकी रोटियां और दलिया बहुत चाव से खाते हैं। इस इलाके में पहले मक्का और ज्वार खाने का चलन था। यहां मक्की माता की पूजा होती है। साठी, सातपानी, दूधमोंगर, खोरवड़ी आदि देसी मक्के की किस्में थीं। इसी संस्कृति व बीजों की विरासत को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिये गांवों में बीज बैंक भी बनाए गए हैं।

यहां देसी बीजों की खासियत बताना उचित होगा। क्योंकि जब खेती की बात होती है तो सिर्फ उत्पादन की ही बात होती है, अन्य पहलुओं पर गौर नहीं किया जाता। बीज खेती का आधार हैं, जीवन हैं, सृजन हैं। और ये बीज आसमान से नहीं टपके हैं। बल्कि हमारे पूर्वजों ने इन्हें विकसित, संरक्षित व संवर्धित किया है। इनकी पैदावार, गुणों, स्वाद व पोषक तत्वों में सुधार करती आ रही है।

गेहूं, धान तथा अन्य खाद्यान्न फसलों के बीज जंगलों में प्राकृतिक रूप से होते थे जिन्हें तब से लेकर अब तक करीब दस हजार वर्षों में कृषि के विकास के साथ विकसित किया गया है। इन बीजों की पहचान, संग्रहण, संरक्षण और संवर्धन करने में किसानों और महिलाओं का योगदान रहा है। कृषि की समृद्धता ने ही हमारे किसानों को समृद्ध बनाया है।

किसानों-आदिवासियों ने ही खेती की कई विधियां-पद्धतियां विकसित की हैं। उन्होंने फसल चक्र बनाया। हमारी कृषि में जैव-विविधता इतनी अधिक थी कि विभिन्न जलवायु, मौसमों और मिट्टी-पानी में उगने वाली अनाजों की किस्में होती थीं। इस खेती की खासियत यह है कि वह प्रकृति से तालमेल, उसके अनुकूल, उसकी गोद में उसी के साथ बढ़ते हुए की जाती है।

देसी बीजों में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है जिससे वह पूरी नष्ट नहीं होती। फसल चक्र अपनाएं तो अगर एक फसल रोग के कारण नष्ट हो जाती है तो दूसरी से मदद मिल जाती है। दूसरी ओर संकर बीजों में प्रतिरोधक क्षमता और कीटों का प्रभाव झेलने की क्षमता बहुत कम होती है।

देसी बीजों में उत्पादन क्षमता की कमी नहीं है बल्कि इसमें बढ़ोत्तरी की काफी सम्भावनाएं हैं। जबकि संकर बीजों से शुरू के एक-दो साल में तो अच्छा उत्पादन होता है, इसके बाद क्रमशः घटने लगता है। उत्पादन बढ़ाने के लिये रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल भी बढ़ाते रहना पड़ता है। कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बार-बार सिंचाई करनी पड़ती है। इस कारण लागत बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति का क्षय होना, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, भूमि का जलस्तर नीचे खिसकते जाना और जहरीला होना, जैव विविधता का नष्ट होना और पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। जहरीने भोजन से स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ रही हैं, यह खबरें कई जगह से आ रही हैं। देसी बीजों के कई लाभ हैं- जैसे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, फसल चक्र से जमीन को फायदा होता है, प्रकृति और किसान का रिश्ता कायम रहता है। इन सबसे खेती टिकाऊ, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित, जैव विविधतापूर्ण होती है और उपज भी बढ़ती जाती है। सभी दृष्टियों से देसी बीज का संरक्षण व संवर्धन जरूरी है। बहरहाल, झाबुआ में बीज बचाने का काम सराहनीय होने के साथ अनुकरणीय भी है। ●

खरीफ फसलों का रकबा 215 लाख हेक्टेयर के पार

राज्यों से मिली सूचनाओं के मुताबिक 1 जुलाई, 2016 तक कुल बुआई क्षेत्र 215.87 लाख हेक्टेयर है, जबकि बीते साल समान अवधि में यह आंकड़ा 279.27 लाख हेक्टेयर था। सूचनाओं के मुताबिक धान की बुआई/रोपाई 47.77 लाख हेक्टेयर, दालों की बुआई 19.85 लाख हेक्टेयर में, मोटे अनाज की बुआई 37.15 लाख हेक्टेयर में, तिलहन की बुआई 28.71 लाख हेक्टेयर में, गन्ने की बुआई 44.38 लाख हेक्टेयर में और कपास की बुआई 30.59 लाख हेक्टेयर में हुई है।

इस साल और बीते साल अभी तक बुआई के आंकड़े (लाख हेक्टेयर में) निम्नलिखित हैं-

फसल	2016-17 में बुआई	2015-16 में बुआई
धान	47.77	47.62
दलहन	19.85	22.25
मोटा अनाज	37.15	43.72
तिलहन	28.71	54.24
गन्ना	44.38	43.68
जूट और मेस्टा	7.43	7.60
कपास	30.59	60.16
कुल	215.87	279.27

ग्वार एक बहु-उपयोगी फसल

ग्वार सूखा सहन करने वाली व गर्म जलवायु की फसल है। यह उन क्षेत्रों में आसानी से उगायी जा सकती है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 30-40 सेंमी तक होती है।

ग्वार एक प्राचीन व बहु-उद्देश्यी रुक्ष दलहन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से बीज, चारा, आहार, सब्जी, हरी खाद, एवं ग्वार गम के रूप में प्रचुरता से होता है। ग्वार बीज के एण्डोस्पर्म से मिलने वाला गम बहुत गुणकारी होता है जिसके कारण इसका गम टेक्सटाइल, पेपर, पैट्रोलियम, माइनिंग, कास्मेटिक, तेल, फार्मास्युटिकल विस्फोटक, फोटोग्राफी, तम्बाकू एवं खाद्य उद्योगा के उपयोग में लाया जाता है। ग्वार कम वर्षा और विपरीत परिस्थितियों वाली जलवायु में भी आसानी से उगायी जा सकती है। भारत विश्व में सबसे अधिक ग्वार की फसल उगाने वाला देश है। विश्व के कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत ग्वार भारत में होता है। हमारे देश के संपूर्ण ग्वार उत्पादक क्षेत्र का करीब 87.7 प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है। जबकि देश के पश्चिमी भाग के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए ग्वार एक अति महत्वपूर्ण फसल है। व्यावसायिक जागरूकता एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बढ़ती मांग और आसमान छूती कीमतों के कारण किसान भाई इसके उत्पादन पर जोर दे रहे हैं।

ग्वार की बीमारियां इसके उत्पादन में कमी का बहुत बड़ा कारण है। उत्तरी-पश्चिमी भारत में पायी जाने वाली ग्वार की प्रमुख बीमारियां, बेक्टीरियल लीफ ब्लाईट (जीवाणु पर्ण अंगमारी), आल्टरनेरिया लीफ स्पाट, रूट रॉट (जड़ विगलन), विल्ट, तना गलन, पूर्ण आसिता एवं नैक्क्रोसिस (किनारी का सूखना) आदि हैं। फसल में होने वाले नुकसान जीवाण ुओं की प्रजाति एवं उनके आक्रमण की तीव्रता पर निर्भर करता है।

बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट सबसे भयंकर बीमारी है जो कि फसल को 40 से 50 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा सकती है। 25 से 30 प्रतिशत नुकसान आल्टरनेरिया लीफ स्पाट बीमारी के कारण होता है। जड़ गलन नामक बीमारी शुष्क भूमि में होने वाली सबसे प्रमुख बीमारी है, इसमें सम्पूर्ण पौधा मर जाता है।

जलवायु- ग्वार सूखा सहन करने वाली व गर्म जलवायु की फसल है। यह उन क्षेत्रों में आसानी से उगायी जा सकती है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 30-40 सेंमी तक होती है। बीजों के अंकुरण से लेकर जड़ों के विकास के लिए 250 से 300 सें. तापमान उपयुक्त होता है। ग्वार एक प्रकाश संवेदनशील फसल है। अत: इस फसल में फूल व फलियों का निर्माण केवल खरीफ के मौसम में ही होता है। अत्यधिक बरसात व ठंड को यह सहन नहीं कर पाती है। शुष्क और अर्ध-शुष्क दोनों दशाओं में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है।

भूमि- ग्वार की खेती के लिए उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। यह फसल सिंचित एवं असिंचित दोनों क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगायी जा सकती है।

खेत की तैयारी- ग्वार की भरपूर पैदावार के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और दुसरी जुताई ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं, जिससे मृदा नमी संरक्षित रहे। जुताई जून के प्रथम पखवाड़े में करनी चाहिए। इस प्रकार तैयार खेत में खरपतवार कम पनपते हैं। साथ ही वर्षा जल का अधिक संचय होता है। इसी समय पूर्णतया सड़ी हुई गोबर की खाद संपूर्ण खेत में बिखेर कर अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें।

बुवाई का समय- ग्रीष्मकालीन फसल की बुवाई के लिए मध्य फरवरी से मार्च का प्रथम पखवाड़ा उपयुक्त समय है। देरी से बुवाई करने पर पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जबकि वर्षा ऋतु की फसल की बुवाई के लिए मध्य जून-मध्य जुलाई उपयुक्त समय है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जुलाई में वर्षा आगमन के साथ ही ग्वार की बुवाई कर देनी चाहिए। अगर ग्वार के बाद दूसरी फसल नहीं लेनी हो तो ग्वार की बुवाई अगस्त के अंत तक भी की जा सकती है। ग्वार की खेती जायद में भी आसानी से की जा सकती है।

बीज की मात्रा- ग्वार के बीज की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस उद्देश्य के लिए उगाया जा रहा है। दाने एवं हरी फलियों के लिए 15 से 18 किग्रा, हरी खाद वाली फसल के लिए 30 से 35 किग्रा तथा चारे वाली फसल के लिए 35 से 40 किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है।

बीजोपचार- बीजों के अच्छे जमाव व फसल को रोगमुक्त रखने के लिए ग्वार के बीजों को सबसे पहले 2.0 ग्राम बाविस्टिन या कैप्टान नामक फफूंदीनाशक दवा से प्रति किलो बीज की दर से अवश्य उपचारित करें। पौधों की जड़ों में गांठों का अधिक निर्माण हो व वायुमंडलीय

नाइट्रोजन का भूमि में अधिक यौगिकीकरण हो, इसके लिए बीजों को राइजोबियम नामक जीवाणु से उपचारित करना बहुत जरूरी है। एक हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हेतु राइजोबियम जीवाणु के 200 ग्राम के दो पैकेट पर्याप्त होते हैं। बीज किसी विश्वसनीय संस्था से खरीदा है तो उसे फफूंदीनाशक दवा से उपचारित करने की आवश्यकता नहीं है। यह बीज पहले से ही उपचारित होता है। भूमि जनित रोग जैसे उखठ़ा की रोकथाम के लिए 2.5 किग्रा ट्राइकोडर्मा प्रजाति 100 किग्रा सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलायें।

बुवाई की विधि- अधिक पैदावार के लिए ग्वार की बुवाई हमेशा पंक्तियों में करें। बुवाई हल के कुड़ों में अथवा सीडड्रिल की सहायता से करें। कुड़ों में पौधों की जड़ों के पास वर्षा जल भी अधिक संग्रहित होता है। इससे पैदावार अधिक मिलती है और फसल की देखभाल करने में भी आसानी रहती है। भरपूर पैदावार हेतु पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंमी तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंमी आदर्श मानी जाती है। बुवाई के समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए जिससे बीज का जमाव शीघ्र व पर्याप्त मात्रा में हो सके। बुवाई उत्तर-दक्षिण दिशाओं में ही करें जिससे सभी पौधों को सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में और लम्बी अवधि तक मिलता रहे। बुवाई कभी भी छिटकवां विधि से न करें। जिन क्षेत्रों में जल निकास की समस्या रहती है वहां जलभराव होने पर पानी को तुरंत खेत से बाहर निकाल दें।

उन्नतशील प्रजातियां:- ग्वार की उन्नतशील प्रजातियों को मुख्यत: तीन भागों दाने, चारे व हरी फलियों के रूप में बांटा जा सकता है। दाने के लिए- मरू ग्वार, आरजीसी-986, आरजीसी-1002, आरजीसी-1066, आरजीसी-936, एच.जी. 2-20, एच.जी. 365, दुर्गाजय, अगेती ग्वार-111, दुर्गापुरा सफेद, एफएस-277, आरजीसी-197, आरजीसी-417

हरी फलियों हेतु- आईसी-1388, पी-28-1-1, गोमा मंजरी, एम-83, पूसा सदाबहार, पूसा मौसमी, पूसा नवबहार, शरद बहार।

हरे चारे हेतु- एचएफजी-119, एचएफजी-156, ग्वार क्रांति, मक ग्वार, बुंदेल ग्वार-1 (आईजीएफआरआई-212-1), बुंदेल ग्वार-2, आरआई-2395-2, बुंदेल ग्वार-3, गोरा-80

खाद एवं उर्वरक प्रबंधन- दलहनी फसल होने के कारण सामान्यत: ग्वार की फसल में उर्वरकों की कम आवश्यकता पड़ती है। ग्वार का बेहतर उत्पादन लेने के लिए 20-25 किग्रा

ग्वार के बीज की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस उद्देश्य के लिए उगाया जा रहा है। दाने एवं हरी फलियों के लिए 15 से 18 किग्रा, हरी खाद वाली फसल के लिए 30 से 35 किग्रा तथा चारे वाली फसल के लिए 35 से 40 किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है।

नाइट्रोजन, 40-50 किग्रा फास्फोरस, 20 किग्रा सल्फर की सिफारिश वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। सभी उर्वरक बुवाई के समय या अंतिम जुताई के समय देने चाहिए। फास्फोरस के प्रयोग से न केवल चारे की उपज में वृद्धि होती है बल्कि उसकी पौष्टिकता भी बढ़ती है। हल्की मृदाओं में 300-400 कुंतल गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग खेत में अंतिम जुताई से पहले समान रूप से बिखेर कर करें। इससे मृदा में नमी संग्रहण व जीवांश की मात्रा बढ़ती है तथा इसके अलावा ग्वार के दाने व फली की गुणवत्ता में बढ़ोतरी एवं मृदा की भौतिक दशा में भी सुधार होता है।

सिंचाई प्रबंधन- सामान्यत: खरीफ ऋतु में बोयी फसल में सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा सामान्य व समय पर न होने पर एक या दो सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। बोने के तीन-चार सप्ताह बाद अच्छी वर्षा न हो तो सिंचाई करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई वर्षा समाप्त होने पर अगस्त या सितम्बर माह में करना आवश्यक है। अगर ग्वार के बाद रबी की फसल लेनी है तो 15 सितंबर बाद सिंचाई न करें। फलियों के लिए उगायी गयी फसल में सिंचाई का विशेष महत्व है। फूल आने और फलियां बनने के समय मृदा में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए अन्यथा फलियों की पैदावार व गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शुष्क व अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में उगायी जाने वाली ग्वार की फसल में समय पर वर्षा न हो तो आवश्यकतानुसार एक-दो सिंचाई देकर किसान भाई अधिक उत्पादन ले सकते हैं। ग्रीष्मकालीन फसल में आवश्यकतानुसार 6-7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए।

खरपतवार नियंत्रण- ग्वार की फसल को खरपतवारों से पूर्णतया मुक्त रखना चाहिए। सामान्यत: फसल बुवाई के 10-12 दिन बाद कई तरह के खरपतवार निकल आते हैं जिनमें मौथा, जंगली जूट, जंगली चरी (बरू) व दूब-घास प्रमुख हैं। ये खरपतवार पोषक तत्वों, नमी, सूर्य का प्रकाश व स्थान के लिए फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं। परिणामस्वरूप पौधे का विकास व वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती है। अत: ग्वार की फसल में समय-समय पर निराई-गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। इससे पौंधे की जड़ों का विकास भी अच्छा होता है तथा जड़ों में वायु संचार भी बढ़ता है। दाने वाली फसल में बेसालिन 1.0 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बुवाई से पूर्व मृदा की ऊपरी 8 से 10 सेंमी सतह में छिड़काव कर खरपतवारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा बुवाई के दो दिन बाद 700 से 800 लीटर पानी में 3 लीटर पेंडिमिथेलीन दवा का घोल बनाकर एक हेक्टेयर में छिड़काव करें। सिंचित क्षेत्र में खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए इमेजाथापर 10 प्रतिशत एस.एल. दवा की 40 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 400-500 लीटर पानी में घोल बनाकर बुवाई के 30-35 दिन बाद छिड़काव करें।

अन्त: फसल प्रणाली- ग्वार की फसल अन्त: फसल प्रणाली के लिए बहुत उपयोगी है। इसे खाद्यान्न फसलों जैसे ज्वार, बाजरा व मक्का के साथ अन्त: फसल के रूप में आसानी से सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अलावा बागवानी फसलों जैसे आंवला, बेर व बेल की दो पंक्तियों के बीच खाली पड़ी जगह पर ग्वार की अन्त: फसल आसानी से ली जा सकती है।

फसल चक्र- सामान्यत: ग्वार शुष्क क्षेत्र में मिश्रित खेती के रूप में अधिक उगाई जाती है केवल ग्वार उगाने के लिये पड़त के बाद ग्वार तथा ग्वार-गेहूं सिंचित क्षेत्रों के लिये उपयुक्त होता है।

बीज उत्पादन- ग्वार के बीज उत्पादन हेतु ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जिसमें पिछले वर्ष ग्वार की खेती न की गई हो तथा खेत के चारों तरफ ग्वार की फसल नहीं उगाई जा रही हो। बीज को उपचारित कर लोहे की टंकियों में भरकर अच्छी प्रकार से बंद कर देना चाहिए। इस बीज को अगले वर्ष बुवाई के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

-डॉ. ऐ. के. मीणा, डॉ. डी. आर. कुम्हार,
एवं डॉ. एस. एल. गोदारा
पादप रोग विज्ञान विभाग, स्वामी
केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,
बीकानेर, राजस्थान

मछली पालन और एक्वाकल्चर में रोजगार के अवसर

मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर स्नातकों के लिए विभिन्न विशेषताओं के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं जिनमें राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां, अकादमिक संस्थान तथा मछली फार्म शामिल हैं। सरकारी एजेंसियां और उद्योग संगठन एक्वाकल्चर कृषक, सीपदार मछली कृषक, हैचरी तकनीशियन, जैविकीय विज्ञान तकनीशियन, मछली अनुसंधान सहायक आदि जैसे पदों पर भर्ती करते हैं।

■ डॉ. अरुण एस. निनावे

मछली पालन कृषिक्षेत्र के तहत एक महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र है, जो लाखों लोगों के लिए प्रोटीन के प्रमुख स्रोत के रूप में उपलब्ध है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में इसका करीब 1.4 प्रतिशत और एक्वाकल्चर क्षेत्र में कुल मिलाकर जीडीपी का 4.5 प्रतिशत योगदान है। व्यापक संदर्भ में इसमें अंतर्देशीय और समुद्री, एक्वाकल्चर, सामग्रियां, नौवहन, महासागर विज्ञान, मछलीघर प्रबंधन, मत्स्य प्रजनन, प्रसंस्करण, समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात और आयात, विशेष उत्पादन और अन्य उत्पाद, अनुसंधान तथा संबद्ध गतिविधियां शामिल होती हैं। भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और अंतर्देशीय मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जैव विविधता से परिपूर्ण भारत के लंबे तटीय क्षेत्र के कारण यहां मछलियों की एक्वा-फार्मिंग और मनोरंजन अथवा उपभोग के लिए क्रसटेशियन तथा पानी में पैदा होने वाले पौधे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इस पर गरीब मछुआरा समुदाय का एक बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए निर्भर होने के कारण यह और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है।

यह अत्यधिक क्षमतावान क्षेत्र है जिसमें एक्वाकल्चर और मेरीकल्चर फार्मिंग व्यवहारों के जरिये मछली पालन के विकास के व्यापक अवसर मौजूद हैं। पिछले छह दशकों के दौरान इस क्षेत्र को अत्यधिक अपेक्षित तकनीक, मानव शक्ति और सक्षम विस्तार कार्मिकों और प्रभावी प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ विकसित किया गया है। अनुसंधान और विकास ने जलजीव विज्ञानियों, फार्म प्रबंधकों, निर्यातकों, व्यापारियों, प्रजनकों और आधुनिक मछुआरों को शामिल करते हुए इस क्षेत्र के उत्पादन स्तर में सुधार और खेती के लिए मत्स्य बीज, उच्च उत्पादक नस्ल और दवाई की उपलब्धता में सराहनीय सहयोग दिया है। अत्यधिक लाभप्रद क्षेत्र होने के कारण इसे मछली पालन और जलीय विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं में रोजगार सृजन और कॅरिअर के अवसरों का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है।

मत्स्य पालन विज्ञान में प्रवेश हेतु पात्रता

मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रवेश पाने के वास्ते मात्स्यिकी स्नातक बनने के इच्छुक व्यक्तियों को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के मात्स्यिकी महाविद्यालयों से 4 वर्षीय डिग्री उत्तीर्ण करनी होती है। मात्स्यिकी विज्ञान में बैचलर पाठयक्रम में प्रवेश के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान और बायो ग्रुप रखने वाले व्यक्ति 10+2 के उपरांत आवेदन कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को मैरिट स्कोर और सीटों की उपलब्धता के अनुसार प्रवेश प्रदान किया जाता है। राज्य के बाहर के उम्मीदवारों को विशेष कोटे

राष्ट्रीय/राज्य मात्स्यिकी संस्थान

1. केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, वर्सोवा, मुंबई, www.cif.edu.in
2. केंद्रीय खारा पानी जलजीव संस्थान, चेन्नई, www.ciba.res.in
3. राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ, www.nbfgr.res.in
4. केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कोच्चि, www.cifnet.nic.in
5. तमिलनाडू फिशरीज यूनिवर्सिटी, नागपट्टिनम, तमिलनाडु, www.tnfu.org.in
6. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल, www.iitkgp.ac.in
7. आंध्र विश्वविद्यालय, तेलीबाग, वाल्टेर, आंध्र प्रदेश, www.andhrauniversity.edu.in
8. गोआ विश्वविद्यालय, www.unigoa.ac.in

राज्य कृषि/पशुचिकित्सा विश्वविद्यालयों के अधीन मात्स्यिकी माहविद्यालय

1. कॉलेज ऑफ फिशरीज, शिरगांव, रत्नागिरी, www.dbskkv.org
2. मात्स्यिकी विज्ञान माहविद्यालय, तेलंगखेडी, नागपुर, http:cofsngp.org
3. कॉलेज ऑफ फिशरीज मंगलौर, कर्नाटक, www.kvafsu.kar.nic.in
4. कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस, पंतनगर, उत्तर प्रदेश, www.gbpuat.ac.in
5. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, www.pau.edu
6. इंस्टीटड्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, थिरूवल्लूर, चेन्नई, http:iftponneri&tnfu.org
7. कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस, कुलिया, पश्चिम बंगाल, www.wbuafscl.ac.in
8. कॉलेज ऑफ फिशरीज, वेरावल, गुजरात, http:www.gsauca.in

की अनुमति होती है जिन्होंने कृषि अनुसंधान परिषद की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की होती है और अध्येतावृत्ति भी प्राप्त कर रहे होते हैं। इसमें जम्मू एवं कश्मीर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए विशेष आरक्षित सीटें होती हैं। मात्स्यिकी विज्ञान स्नातक पाठयक्रम में अंतर्देशीय एक्वाकल्चर, फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर, मेरीकल्चर, औद्योगिक मत्स्यपालन, मछली प्रसंस्करण और फसल उपरांत प्रौद्योगिकी, मत्स्य पोषण, पैथोलॉजी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विस्तार जैसे विषय शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम में व्यवहारिक अनुभव भी शामिल होता है, जैसे कि समुद्री नौकाओं पर मछली पकड़ना और डाटा संग्रह तथा प्रसंस्करण संयंत्रों में मात्स्यिकी आदि। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शैक्षणिक कार्यक्रम के जरिये ग्रामीण कृषि कार्यानुभव (आरएडब्ल्यू) के अधीन फार्म अध्ययनों से छात्रों को एक्वा-फार्मों, हैचरी, मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयों, मूल्यवर्द्धन, संसाधन प्रबंधन आदि पर व्यावहारिक ज्ञान हासिल करने में सहायता मिलती है।

उच्चतर शिक्षा

मत्स्य विज्ञान में बैचलर डिग्री पूर्ण करने के उपरांत उम्मीदवार मत्स्य विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को चुन सकते हैं जिसके लिए भारत में केंद्रीय संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित आठ मात्स्यिकी संस्थान हैं, जिनके नाम हैं- सीआईएफई, सीआईबीए, सीआईएफए, सीएमएफआरआई, सीआईएफटी, सीआईएफआरआई, एनबीएफजीआर और डीसीएफआर। ये संस्थान अपने अनुसंधान कार्यक्रम के अलावा मछली पकड़ने, खेती, मूल्य विस्तार प्रसंस्करण, संग्रह, संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन संस्थानों में छात्र स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर तक की विशेषीकृत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इनके अलावा स्वतंत्र पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विद्यालयों के अधीन करीब 18 मात्स्यिकी महाविद्यालय और राज्य कृषि विश्वविद्यालय भी मात्स्यिकी विज्ञान में बैचलर तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। अवसंरचना और अत्याधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर मात्स्यिकी महाविद्यालय अपनी व्यवस्था के अधीन पीएचडी पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। कई विद्यालयों के जरिये जलजीव विज्ञान और मात्स्यिकी में मास्टर और पीएचडी कार्यक्रम उपलब्ध है। छात्र अपनी रुचि के अनुरूप अनुसंधान का विषयक्षेत्र चुन सकते है, जैसे कि मत्स्य पोषण, जल गुणवत्ता, जलजीव विज्ञान इंजीनियरिंग, मछली आनुवंशिकी, अंडा उत्पादन और मत्स्य पैथोलॉजी। ज्यादातर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शोधपत्र अपेक्षित होते हैं जबकि पीएचडी छात्रों के लिए मुख्यत: एक पूर्ण शोध-निबंध अपेक्षित होता है। मछली पालन और प्रजनन, एकीकृत मत्स्य-पशुधन फार्मिंग, मत्स्य स्वास्थ्य प्रबंधन और पोषण, सघन मत्स्य फार्मिंग तथा पर्यावरण प्रबंधन सहित फसल उपरांत और प्रसंस्करण के विकास जैसे क्षेत्रों में शोध गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

मात्स्यिकी स्नातक और उच्चतर अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को आकर्षक वेतन और लाभों के साथ अच्छे रोजगार अवसर प्राप्त होते हैं। सरकारी संस्थानों में उन्हें सहायक निदेशक, अनुसंधान सहायक और मात्स्यिकी निरीक्षक आदि के तौर पर नियुक्त किया जाता है।

फार्म तथा कौशल आधारित प्रशिक्षण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कृषि विज्ञान केंद्र अपने संस्थानों के सहयोग से प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं और एनसीईआरटी से सक्रिय सहयोग से 10+2 स्तर पर मत्स्य पालन को व्यावसायिक पाठयक्रम के तौर पर शामिल करते हैं। तटीय राज्यों में मछुआरा बहुल गांवों में मछुआरों के लिए नियमित कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इंस्टीटड्यूट ऑफ फिशरीज नोटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग (सीआईएफएनईटी) द्वारा भी गहरे समुद्र में मछली पकड़ने तथा नौवाहन विषय पर प्रशिक्षण संचालित किये जाते हैं। भारत में विभिन्न एजेंसियों द्वारा स्कूबा डाइविंग में लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं जिनसे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और संसाधन उपयोग, मानचित्रीकरण तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में रोजगार सृजन में सहायता मिलती है।

रोजगार के अवसर

मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर स्नातकों के लिए विभिन्न विशेषताओं के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं जिनमें राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां, अकादमिक संस्थान तथा मछली फार्म शामिल हैं। सरकारी एजेंसियां और उद्योग संगठन एक्वाकल्चर कृषक, सीपदार मछली कृषक, हैचरी तकनीशियन, जैविकीय विज्ञान तकनीशियन, मछली अनुसंधान सहायक आदि जैसे पदों पर भर्ती करते हैं। एक्वाकल्चर से लेकर मछलियों की समुद्री खेती, सीपदार मछली और समुद्री उत्पदों के क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार के बहुत से विकल्प मौजूद हैं। प्राथमिक स्तर के एक्वाकल्चर रोजगारों के लिए हाई स्कूल डिप्लोमा अथवा एक्वाकल्चर एवं मात्स्यिकी में अंडर-ग्रेजुएट डिग्री अपेक्षित होती है परंतु अधिक उन्नत पदों के लिए स्नातकोत्तर अथवा पीएचडी डिग्री की आवश्यकता होती है। राज्य सरकारों में मछली पालन विभाग में मात्स्यिकी स्नातकों के लिए सहायक मात्स्यिकी विकास अधिकारी तथा मात्स्यिकी विकास अधिकारी और जिला मात्स्यिकी विकास अधिकारी के पद उपलब्ध होते हैं। एक्वाकल्चर फार्मिंग में उच्च विद्यालय डिप्लोमा धारकों के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। लेकिन इस उद्योग में नियोक्ताओं की संख्या में वृद्धि से सेकेंडरी उपरांत उम्मीदवारों को कुछ पदों के लिए रोजगार में वरीयता दी जाती है।

विभिन्न प्रकार के एक्वाकल्चर रोजगारों के लिए अध्ययन के अपेक्षित कौशल और ज्ञान उपलब्ध करवाने के लिए विदेशो में मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर में एसोसिएट और बैचलर डिग्री कार्यक्रम उपलब्ध करवाये जाते हैं। द्विवर्षीय कार्यक्रमों में छात्र स्नातक के उपरांत रोजगार बाजार में प्रवेश के लिए अनुप्रयुक्त विज्ञान डिग्री के एसोसिएट के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और इसे चार वर्षीय अकादमिक कार्यक्रम में तब्दील करने के लिए विज्ञान में फैलोशिप हासिल कर सकते हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन और यूरोपीय देशों आदि में मात्स्यिकी में उच्चतर शिक्षा के लिए संभावना के अलावा, खाड़ी और अफ्रीकी देशों में भी एक्वाकल्चर तथा प्रसंस्करण क्षेत्रों में मात्स्यिकी विशेषज्ञों की मांग है। विदेशों में एक्वाकल्चर, निर्यात और आयात के क्षेत्र में व्यापार संचालित करने वाले बहुत से मात्स्यिकी स्नातक मौजूद हैं।

मात्स्यिकी स्नातक और उच्चतर अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को आकर्षक वेतन और लाभों के साथ अच्छे रोजगार अवसर प्राप्त होते हैं। सरकारी संस्थानों में उन्हें सहायक निदेशक, अनुसंधान सहायक और मात्स्यिकी निरीक्षक आदि के तौर पर नियुक्त किया जाता है। सरकारी क्षेत्र में निजी क्षेत्र की तुलना में वेतन थोड़ा कम जरूर होता है लेकिन वह स्थाई रोजगार होता है। निजी क्षेत्र में मात्स्यिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर के लिए गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी, मत्स्य प्रोसेसर, एक्वाकल्चररिस्ट, फार्म सहायक, प्रबंधक आदि के अनेक अवसर उपलबध होते हैं। इन्हें उम्मीदवार की रोजगार प्रकृति और विशेषज्ञता के अनुरूप भिन्न-भिन्न वेतन प्रदान किया जाता है। ●

'कृषि चौपाल' ने आयोजित किया एक दिवसीय सेमिनार

स्वतंत्रता सेनानी, गोवा मुक्ति आंदोलन के अग्रणी एवं उत्तराखंड आंदोलन के प्रणेता स्व. ऋषिबल्लभ सुंदरियाल की 42वीं पुण्यतिथि पर ऋषिबल्लभ सुंदरियाल महाविद्यालय चौबट्टाखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में 'कृषि चौपाल' संस्था द्वारा एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार का विषय था- उत्तराखंड में घटती खेती और पर्यावरणीय संकट। 'कृषि चौपाल' के साथ-साथ इस सेमिनार में अन्य सामाजिक संस्थाओं हिमालय बचाओ-हिमालय बसाओ अभियान, ऋषिवल्लभ सुंदरियाल विचार मंच, क्रियेटिव उत्तराखंड, म्यर पहाड़ एवं महिला मंगल दल ग्राम मजगांव ने भी भागीदारी की। सेमिनार में भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर उत्तराखंड आंदोलन के संघर्ष से रूबरू कराती एक प्रदर्शनी भी लगाई गयी। इस दौरान दो मनीषियों स्व. भैरवदत्त धूलिया और कॉमरेड पी.सी. जोशी के पोस्टर भी जारी किए गए। सेमिनार में क्षेत्रीय विधायक तीरथ सिंह रावत, पहाड़ में चकबंदी के प्रणेता गणेश सिंह गरीब, मलेथा आंदोलन के प्रमुख समीर रतूड़ी, वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी, शिक्षक मुकेश बहुगुणा, 'उत्तराखंड जागरण' समाचार पत्र के संपादक सतेन्द्र सिंह रावत, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े दिनेश जोशी, सामाजिक सरोकारों से जुड़े माधवानन्द शर्मा, 'कृषि चौपाल' संस्था के अध्यक्ष महेन्द्र बोरा, पूर्व प्रमुख एवं भाजपा नेता पुष्कर जोशी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े अमित कौल, सामाजिक कार्यकर्ता राकेश सभरवाल (चीनू भाई), ग्राम सभा मजगांव के प्रधान दिनेश सुंदरियाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनीष सुंदरियाल, पूर्व सैनिक/अर्द्ध सैनिक प्रकोष्ठ एकेश्वर पोखड़ा ब्लॉक के महामंत्री मित्रेश सुंदरियाल, जिला पंचायत सदस्य पौड़ी प्रवेश सुंदरियाल तथा क्षेत्र की काश्तकार महिलाओं एवं पुरुषों ने उत्साह से भाग लिया।

सेमिनार की अध्यक्षता पूर्व सैनिक/अर्द्ध सैनिक प्रकोष्ठ एकेश्वर पोखड़ा ब्लॉक के अध्यक्ष ताजबर सिंह ने की। संचालन स्व. ऋषिबल्लभ सुंदरियाल के सुपुत्र एवं श्रमिक संगठनों के प्रखर नेता प्रेम सुंदरियाल ने किया।

इस मौके पर स्थानीय विधायक तीरथ सिंह रावत ने कहा कि गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ाई के दौरान स्व. सुंदरियाल का संपर्क देश के महान क्रांतिकारियों से हुआ। भूमिगत संगठनों के लिए काम करने और जेल यात्राएं करने से उनकी शिक्षा और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी। भारतीय जन संघ, जनतांत्रिक जन संघ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल जैसे दलों के गठन में उनकी प्रमुख भूमिका रही। पश्चिमी उप्र. के किसान आंदोलन और उत्तराखंड राज्य आंदोलन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए वे आज याद किये जाते हैं।

इस मौके पर वक्ताओं ने स्व. सुंदरियाल के विचारों को आत्मसात करने पर बल देते हुए कहा कि आज के समय में हमें उस विचार को ताकत के साथ आगे ले जाना चाहिए जिसे साठ के दशक में सुंदरियाल ने महसूस किया कि देश को बचाने के लिए हिमालय का बचना जरूरी है। सिर्फ सरकार की नीतियों के भरोसे हिमालय को नहीं बसाया जा सकता और न ही

पलायन रोका जा सकता है जब तक वहां का आम आदमी इसमें अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा। पलायन के नाम पर छोटे नगरों-कस्बों और बाजारों में होने वाले पलायन से गांव खाली हो रहे हैं। पहाड़ों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का अभाव ही पलायन का मुख्य कारण है। वक्ताओं ने कहा कि हिमालय सिर्फ उत्तराखण्ड तक ही सीमित नहीं है। हिमालय के दोनों ओर एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। हिमालयी राज्यों की समस्याएं एक सी हैं। वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के बाद डॉ. रामलोहिया ने जहां हिमालय बचाओ की बात की थी, वहीं हिमालयी राज्यों के विकास के लिए अलग से मंत्रालय गठन की मांग भी उठी थी। लेकिन केन्द्र में सत्तारूढ़ अब तक की सरकारों ने हिमालय क्षेत्र खासतौर पर उत्तराखंड की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। वक्ताओं ने कहा कि आज जिस तरह से हमारे संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिशें हो रही हैं, ये अगर जारी रहीं तो हिमालय नहीं बचेगा। इसलिए सुंदरियाल जी द्वारा उठाई गयी आवाज 'हिमालय बचाओ, हिमालय बसाओ' को आगे बढ़ाने की सख्त जरूरत है।

वक्ताओं ने कहा कि जब तक हम खेती की वर्तमान व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, तब तक राज्य का विकास सम्भव नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में चकबंदी लागू किये बिना विकास संभव नहीं है और लोगों को अपने आप आगे आकर चकबंदी का समर्थन करना चाहिए। राज्य में खेती में आ रहे संकट के लिए वक्ताओं ने सरकार को जिम्मेदार माना। उन्होंने कहा कि राज्य की कृषि उपयोग भूमि को सरकार ने सिडकुल के नाम पर उद्योगपतियों को कौड़ियों के दाम बेच दिया और अब सुदूर पहाड़ों की जमीन भी विकास के नाम पर बेची जा रही है।

वक्ताओं ने कहा कि सुंदरियाल ही थे जिन्होंने उत्तराखंड राज्य जैसे विचार को मूर्त रूप देने की पहल की। उन्होंने पलायन से लेकर लगातार सूख रहे पानी के स्रोतों पर अपनी चिंता जताई और कहा कि हमारे जीवन का आधार रही नदियां अब बिजली के नाम पर हमारे खिलाफ खड़ी की जा रही हैं। यह जनता के साथ सबसे बड़ा छलावा है, इसलिये आज सुंदरियाल जी याद आते हैं। सन् 1968 एवं 1972 में दिल्ली के वोट क्लब पर विशाल जनसमूह का नेतृत्व करते हुए उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मील का पत्थर स्थापित किया। परंतु उत्तराखंड सरकार राज्य आंदोलन के इस प्रणेता को भुला चुकी है।

-दिनेश जोशी

कंपनी गतिविधियां

'एसबीआई मिंगल' से और आसान हो जाएगी बैंकिंग

नेट फ्रैंडली और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के शौकीन लोगों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एसबीआई मिंगल नाम से एक आकर्षक योजना शुरू करने की घोषणा की गयी है जो नेट बैंकिंग को और भी सुविधाजनक बना देंगी।

एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने 61वें स्टेट बैंक दिवस पर एक नई पहल की है। इसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बैंक फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफार्म के जरिए एसएमएस अलर्ट, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के लिए पंजीकरण तथा चैकबुक इशू कराने जैसी कई सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है।

इस सोशल मीडिया फ्रैंडली सुविधा को भारतीय स्टेट बैंक ने 'एसबीआई मिंगल' के नाम से शुरू करने का निर्णय लिया है। बैंक के ग्राहक इसके माध्यम से विभिन्न बैंकिंग सेवाओं का उपयोग फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए कर सकेंगे। बैंक ने एक बयान जारी करके बताया है कि एसबीआई मिंगल के जरिए बैंक के ग्राहक अपने फेसबुक और ट्विटर एकाउंटस के साथ अपने बैंक को जोड़कर विभिन्न बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे।

किसानों की पहली पसंद अंगद डीजल हल

किसानों के लिए अंगद डीजल हल वरदान साबित हो रहा है। इससे और इसमें जुड़ने वाले उपकरण की सहायता से खेती के सभी काम जैसे जुताई, गुड़ाई, बिजाई, स्प्रे (छिड़काव), सिंचाई, कटाई आदि काम कम समय और कम मेहनत में किये जा सकते हैं। यह मशीन सिर्फ गेहूं, चावल, गन्ना, कपास ही नहीं, बल्कि सब्जी, बागवानी फसलों की खेती को भी आसान बनाती है। इस मशीन में हल, रोटावेटर, कल्टीवेटर, लेवेलर (पाटा), रिजर, रिपर, सीड ड्रिल, पोटेटो डीगर, वाटर पम्प, स्प्रे पम्प आदि कृषि उपकरण जोड़े जा सकते हैं। साथ ही धान के खेत तैयार करते समय पहिये पानी में स्लिप न हों और खेत में कीचड़ सही से बने इसके लिए इसमें पडलिंग रोटावेटर भी जोड़ा जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्र के उन इलाकों में जहां ट्रैक्टर नहीं पहुंच सकता और खेती में बड़ी दिक्कतें आती हैं, वहां भी इस मशीन के द्वारा खेती में नए मुकाम हासिल हुए हैं। गन्ने की खेती के लिए यह नंबर वन मशीन है। इससे गन्ने की खेती में निराई-गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाना, स्प्रे करना और पानी देने का काम किया जाता है। कुल मिलाकर यह डीजल से चलने वाली किसानों की अत्याधुनिक मशीन है। यह बहु-कार्योपयोगी मशीन महज एक लाख रुपये की कीमत में खरीदी जा सकती है। अंगद की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की आज इसके वितरक-डीलर पूरे देश भर में फैले हुए हैं और इस मशीन को **www.lalajee.in** पर ऑनलाइन भी बुक किया जा रहा है।

पशु पालकों के लिए नाबार्ड की पीडीडीएस योजना

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु पालकों के लिए पीडीडीएस योजना शुरू की है। इसके तहत पशु पालकों को ऋण दिया जायेगा। नाबार्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2016-17 के लिए देश में 140 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। सामान्य वर्ग के लिए 110 करोड़ रुपये, एससी वर्ग के लिए 17 करोड़ रुपये और उत्तरी राज्यों के लिए 13 करोड़ रूपये का बजट है। कोई स्वयं सहायता समूह डेयरी फार्म खोलने के लिए छह लाख रुपये का ऋण ले सकता है। साढ़े पांच लाख रूपये दूध निकलने की मशीन के लिए, कोल्ड रूम के लिए 31 लाख रूपये तक का ऋण मिल सकता है। सामान्य वर्ग के उपभोगता को 25 और एससी व एसटी को 33 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।

फसल बीमा योजना में शामिल हुई चारों जनरल इंश्योरेंस कंपनियां

अब निजी क्षेत्र की चारों बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां भी सरकारी फसल बीमा योजनाओं को बेच सकेंगी। सरकार ने इन कंपनियों को भी योजनाओं में भागीदार बनाया है। बता दें कि सरकार ने पहले प्राइवेट सेक्टर की 11 कंपनियों को उनकी क्रॉप इंश्योरेंस में अच्छा अनुभव जानते हुए योजना में शामिल कर लिया था, जबकि पब्लिक सेक्टर की एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का जनरल इंश्योरेंस में 50 फीसदी मार्केट शेयर है, इसलिए सरकार ने योजना में इन्हें भी शामिल कर लिया। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के चेयरमैन जी. श्रीनिवासन का कहना है कि खरीफ सीजन शुरू हो चुका है। फिलहाल भारत में 24 से 25 फीसदी फसलें ही बीमा कवर में आती हैं, लेकिन आने वाले समय में सरकार चाहती है कि इसे 50 फीसदी से अधिक किया जाए। सरकार और अनुभवी कंपनियों के साथ मिलकर हमारा भी यही टार्गेट रहेगा कि किसानों की फसलों को ज्यादा से ज्यादा कवर मिल सके।

अब चाय होगी महंगी

महंगाई की मार चाय पर भी पड़ सकती है। दरअसल दक्षिण भारत में भारी बारिश की वजह से चाय की फसल को नुकसान हुआ, जिस कारण चाय उत्पादन में 15 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। टी ट्रस्ट के ऑनर कमल ठुकराल का मानना है कि कम उत्पादन की वजह से

आने वाले दिनों में चाय की कीमतें बढ़ने की संभावना है। 'जयश्री टी' के एमडी डी. पी. माहेश्वरी ने बताया कि भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ, जिस कारण प्रोडक्शन में कमी देखी गई है। 'मित्तल टी' के विक्रम मित्तल ने कहा कि 2015-16 में भारत का चाय उत्पादन 123.31 करोड़ किलो था और देश ने 23.29 करोड़ किलो चाय का निर्यात किया, लेकिन इस बार दक्षिण राज्यों में प्रतिकूल मौसम की वजह से चाय उत्पादन कम हुआ है।

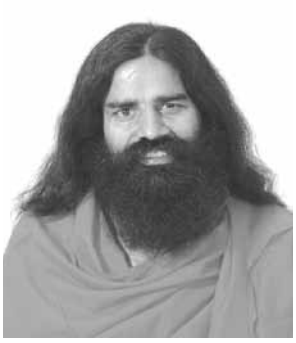

पतंजलि लाएगी नए डेयरी प्रोडक्ट्स

योगगुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि अब नए डेयरी प्रोडक्ट्स बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अगले साल तक कुल 10,000 करोड़ रपये के कारोबार का लक्ष्य रखा है। रामदेव ने कहा, श्हम दूध जैसे और डेयरी उत्पाद लाएंगे, हम 3-4 डेयरी परियोजनाएं स्थापित करेंगे, ताकि किसानों को सशक्त बनाया जाए और लोगों को बिना मिलावट वाले सामान मिले।श उन्होंने कहा कि पतंजलि समूह प्राकृतिक औषधि, प्राकृतिक खाद्य पदार्थ, डेयरी उत्पाद, पशु चारा तथा प्राकृतिक खाद जैसे छह क्षेत्रों पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा, 'हम पशु आहार भी लेकर आएंगे, जिसमें कोई यूरिया नहीं होगा। इससे मवेशियों को लाभ होगा।' रामदेव ने दावा किया कि मवेशियों को जो आहार दिया जाता है, उसमें 1-4 प्रतिशत यूरिया होता है। जिससे देश में 50 प्रतिशत गायों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। योगगुरु ने यह भी कहा कि पंतजलि समूह फसलों के लिए प्राकृतिक खाद भी लाएगा, जिसमें सूक्ष्म खनिज, विटामिन आदि होंगे।

TATA

TATA CHEMICALS LIMITED

टाटा केमिकल्स का 'जीत की खरीद'

टाटा केमिकल्स ने किसानों के लिए 'जीत की खरीद' नामक नया ऑफर प्रस्तुत किया है जिसके अंतर्गत टाटा केमिकल्स के दक्ष बाजरा बी-3311 और दक्ष संकर धान पी-221 बीजों की खरीद पर किसानों को आकर्षक उपहार जीतने का सुनहरा मौका मिलेगा। 5 अगस्त 2016 तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण है इसमें मिलने वाले अत्याधुनिक तकनीक वाले न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर और रोटावेटर के बम्पर ईनाम। इस प्रतियोगिता के दौरान दक्ष बीज खरीदने वाले दो योग्य विजेता पाएंगे 35 हॉर्स पावर का न्यू हॉलैंड 3032 ट्रैक्टर और अन्य दो विजेता घर ले जाएंगे 6 फुट न्यू हॉलैंड रोटावेटर।

सरकार लाई सीएनजी से चलाने वाले दुपहिया वाहन

ऑटो रिक्शा, कार और बसों के बाद अब सरकार की अगली योजना दुपहिया वाहनों को भी सीएनजी से चलाने की है। हरित अभियान की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए पिछले महीने सरकार ने सीएनजी दुपहिया वाहनों के पायलट चरण का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लैक्स स्थित सीएनजी स्टेशन पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि इस पहल को सीएनजी वितरक कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) और प्राकृतिक गैस कंपनी गेल (इंडिया) द्वारा 'हवा बदलो' अभियान के अंतर्गत चलाया जा रहा है।

एनटीपीसी देगी दिव्यांगों को सहारा

विद्युत उत्पादन में भारत की सबसे बड़ी कम्पनी एनटीपीसी ने आगामी 3 वर्षों की अवधि के लिए एनटीपीसी स्टेशनों/परियोजनाओं के आसपास रहने वाले लगभग 5000 दिव्यांगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिमको) के साथ एक समझौता किया है। एलिमको, एनटीपीसी को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और दिव्यांग लाभार्थियों की पहचान, उनके लिए आवश्यक सहायता तथा सहायक यन्त्रों की पहचान के लिए मुल्यांकन अध्ययन करेगा। इन सहायता और सहायक यन्त्रों को प्राप्त करने के साथ ही साथ एनटीपीसी स्टेशनों के आस-पास के शिविरों में इनका वितरण भी समझौते का भाग है। एलिमको, प्रोस्थेटिक और ओर्थोटिक फिटमेंट (कृत्रिम अस्थि संशोधन उपकरण) में नए प्रचलन के बारे में पुनर्वास कार्मिकों को आधुनिक जानकारी देने के लिए एनटीपीसी के कुछ परियोजना क्षेत्रों में विकलांग (दिव्यांग) पुनर्वास केंद्रों पर उनके प्रशिक्षण के लिए भी सहायता करेगा। एस. के. जैन, कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन, आरएंडआर, सीएसआर) एनटीपीसी तथा डी.आर. सरीन, मुख्य कार्यकारी निदेशक, एलिमको ने नई दिल्ली में यू.पी. पाणी, निदेशक (मानव संसाधन) एनटीपीसी की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किया।

पोटाश खाद के दाम में 200 रुपए प्रति बैग की कटौती

देश की सबसे बड़ी पोटाश खाद कंपनी इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) ने पोटाश खाद के दामों में 200 रुपए प्रति बैग की कटौती की है। अब किसानों को पोटाश का 50 किलोग्राम का बैग 550 रुपए में मिलेगा। कंपनी ने पिछले एक महीने से भी कम समय में पोटाश खाद के दामों में कटौती की है। खाद के दाम पांच साल के निम्मतम स्तर पर आ गए हैं। कंपनी के मैनेजिंग डॉयरेक्टर पीएस

गहलौत ने बताया कि कंपनी इस समय काफी कम कीमत में पोटाश के लवण का इंपोर्ट कर रही है। ऐसे में इसका सीधा लाभ किसानों को मिलना चाहिए, जो कि दो सालों से सूखे का सामना कर रहे हैं।

सुरक्षित सवारी और बेरोजगारी दूर करेगी अंगद ई-बग्गी

कृषि मशीनरी के 11 वर्षों के अनुभव के बाद एसएएस मोटर्स ने जीवन स्तर में सुधार की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए दूर-दराज परिवहन समस्या के निदान के लिए भारत का पहला स्वदेशी डिजाइन निर्मित आईसीएटी (आईकेट) अनुमोदित तिपहिया बैटरी रिक्शा बनाया है। यह तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण पर एक तरफ जहां नियंत्रण लगाएगा, वहीं दूसरी तरफ जेंडर फ्रैंडली होने के कारण महिलाएं इसे चलाकर अपनी आर्थिक स्थिति में इजाफा कर सकेंगी और सवारी (महिलाएं और बच्चे) भी महिला चालक होने पर अपने को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे।

अंगद ई-बग्गी की खास विशेषता यह है की इसमें प्रयुक्त उच्च तकनीक और विभिन्न गुणवत्तापूर्ण सामानों के उचित संयोजन और भार नियंत्रण के द्वारा इसकी कार्यक्षमता, बैटरी की लाइफ और वाहन के माइलेज को बढ़ाया जा सकता है। इसे चलाकर जहां साधारण रिक्शा चालक बिना अधिक श्रम के ज्यादा सवारी ढो सकेंगे, वहीं बेरोजगार इससे अपनी जीविका पा सकेंगे और दूर-दराज के परिवहन से न जुड़े क्षेत्रों में भी परिवहन सुगम हो सकेगा। एसएएस मोटर्स का अंगद ई-बग्गी को निर्मित करने का मुख्य उद्देश पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना है और साधारण रिक्शा चालकों को एक आदमी द्वारा दूसरे आदमी को खींचे जाने वाली प्रथा से मुक्ति दिलाना है।

महिंद्रा के नए युवो ट्रैक्टर्स

महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने अपने नए युवो ट्रैक्टर्स की रेंज भारतीय बाजार में लॉन्च की है। महिंद्रा युवो ट्रैक्टर रेंज को पांच मॉडल्स में लॉन्च किया है। महिन्द्रा के इन टैक्टर्स की कीमत 4.99 लाख से 6.49 लाख रुपए है। महिंद्रा युवो रेंज के ट्रैक्टर्स एक नए प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं और ओवर 30 डिफरेंट फार्मिंग एप्लीकेशंस को एकम्पलिश करने के लिए हाईली वर्सेटाइल हैं। महिंद्रा युवो ट्रैक्टर हार्ड सोइल सरफेस पर भी अनस्टॉपेबल वर्क करते हैं और 400 ऑवर सर्विस इंटरवेल के साथ आते हैं, जो कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप को घटाता है। एनहेंस्ड कूलिंग फेसिलिटी फार्मर्स को विटाउट इंजन हीटिंग अप लोंगर ऑवर्स के लिए वर्क करने को अलॉउ करता है। प्रीसिजन हाईड्रोलिक आर्म विद हाई टेक कंट्रोल वॉल्व कंट्रोल एंड एक्यूरेसी ऑफ डेप्थ ऑफर करता है। कैबिन कफर्टेबल सीट व ऑपरेटर प्लेटफॉर्म के साथ ऑक्यूपेंट के लिए अटमोस्ट कफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए वैल डिजाइन्ड किया गया है, व्हाइल लीवर्स व पैडल्स एफर्टलैस ड्राइविंग को ईजी बनाते हैं।

इफको ने उर्वरक कीमतों में की कटौती

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) ने देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। कंपनी ने डीएपी और एनपीके उर्वरक की कीमतों में 1,000 रुपये प्रति टन की कटौती कर दी है, जिससे डीएपी और एनपीके दोनों के दाम 50 रुपये प्रति बोरी कम हो जाएंगे। इफको कंपनी की ओर से अपनी 50वीं वर्षगांठ पर किसानों को यह ऑफर दिया गया। इफको हर साल करीब 53 लाख टन डीएपी और एनपीके की बिक्री करता है। इन उर्वरकों के दाम घटाने से इफको पर 530 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। कंपनी के एमडी और सीईओ यू. एस. अवस्थी ने कहा कि कंपनी के 50 साल पूरे होने पर किसानों को तोहफे में ये कटौती की राहत देने की कोशिश की गई है।

punjab national bank

पीएनबी ने सीमित समय के लिए फीस माफ की

होमलोन और कार लोन लेने की तैयारी कर रहे कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर है। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने नये आवास व कार लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन फीस को माफ करने की घोषणा की है। यह फीस माफी सीमित समय के लिए है। बैंक के मुताबिक सितंबर के अंत तक होम और कार लोन लेने वाले ग्राहकों को इस फीस माफी का लाभ मिलेगा। बैंक के एक बयान में कहा गया है कि तीन महीने की यह मानसून छूट 30 सितंबर तक जारी रहेगी। इसके अनुसार इस अवधि के दौरान बैंक एक जुलाई से 30 सितंबर तक आवास व कार ऋणों के लिए प्रसंस्करण शुल्कों व दस्तावेज शुल्कों में पूरी तरह छूट देगा। इसके अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान बैंक खुदरा विशेषकर आवास, कार तथा शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। बैंक का दावा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में इस तरह की पेशकश करने वाला यह पहला बैंक है।

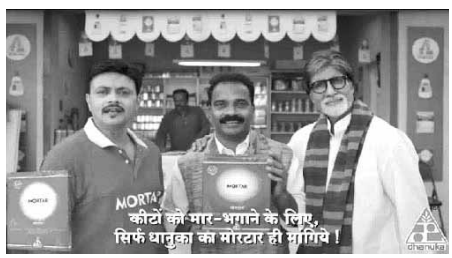

धानुका के लिए विज्ञापन करेंगे अमिताभ

एग्रोकेमिकल बनाने वाली भारतीय कपंनी 'धानुका एग्रीटेक लिमिटेड' ने अपनी विज्ञापन सीरीज के लिए अमिताभ बच्चन को साइन किया है। इन विज्ञापनों में बिग-बी किसानों को अपनी फसलों के लिए सही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते नजर आएंगे। अमिताभ किसानों को अलग-अलग फसलों के लिए धनजाइम गोल्ड, मैक्स सॉय, मोर्टर, सकुरा और कवर सहित कई प्रोडक्ट के इस्तेमाल के लिए

मार्गदर्शन करते नजर आएंगे। 'धानुका एग्रीटेक लिमिटेड' के एमडी एम.के. धानुका ने कहा कि धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ज्ञान आधारित और विकास संबंधी गतिविधियों के जरिये दशकों से भारतीय किसानों की जिंदगी में विकासशील बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अमिताभ केवल एक कुशल कलाकार ही नहीं बल्कि उनकी साख और विश्वसनीयता भी ऊंचे दर्जे की है। वह धानुका और ब्रांड के संदेश के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं।

दक्षिण अफ्रीका में सिप्ला लगाएगी संयंत्र

देसी फार्मा कंपनी सिप्ला, दक्षिण अफ्रीका में एक बायोटेक संयंत्र लगाने के लिए तकरीबन 600 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। कंपनी का उद्देश्य कैंसर दवाओं को किफायती दामों में उपलब्धा करा बाजार में अपनी पहचान स्थापित करने की है। सिप्ला बायोटेक, सिप्ला की एक सहयोगी इकाई है जो अपने इस संयंत्र को डरबन के विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापति करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि संयंत्र में उत्पादन वर्ष 2018 से शुरू कर दिया जाएगा। सिप्ला ने दक्षिण अफ्रीकी दवा कंपनी को वर्ष 2013 में मेडप्रो से खरीदा था। यह कंपनी का विदेश में सबसे बड़ा अधिग्रहण था।

चंद्रभान ने उतारा 'दलित फूड्स'

दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद ने 'दलित फूड्स' के नाम से खाद्य उत्पादों की एक सिरीज शुरू की है। इस सिरीज के तहत आम का आचार, हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर जैसे उत्पाद ऑन लाइन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। चंद्रभान के मुताबिक, फिलहाल उनके उत्पाद ई-कॉमर्स के लिए उपलब्ध हैं। इसके लिए उन्होंने दलित फूड्स डॉट कॉम और दलित शॉप डॉट कॉम नाम से दो वेबसाइट शुरू की हैं। चंद्रभान प्रसाद ने पांच लाख रुपये के निवेश के साथ दलित फूड्स नामक ब्राण्ड की शुरुआत की है। चंद्रभान प्रसाद कहते हैं कि जो आजकल हेल्दी डायट है, वो एक-दो पीढ़ी पहले तक दलितों का मुख्य भोजन हुआ करता था। आज डायबिटीज और हृदय रोग के मरीज जो जौ और बाजरा खा रहे हैं, वही दलितों का मुख्य भोजन था। ●

दूसरे सेशन में भाग लेने वाले प्रतिभागी: राकेश गुप्ता (पीएनबी), राहुल जे. मित्तल (मार्गदर्शक फाइनेंसियल), विजय सरदाना (सेबी), गिरीश नायर (वर्ल्ड बैंक), राज बेंहलकर (एनसीडीईएक्स), आशीष अग्रवाल (पीएचडी), बीवीएस प्रसाद (नाबार्ड)

पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और नाबार्ड ने मिलकर '2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका' विषय पर 5 जुलाई को दिल्ली स्थित पीएचडी हाउस में एक सेमिनार का आयोजन किया। दो भागों में आयोजित इस बैठक में केंद्र सरकार, बैंकों, वित्तीय संस्थानों सहित कई अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया और सभी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये। इस कार्यक्रम में 'कृषि चौपाल' ने बतौर मीडिया पार्टनर भूमिका निभायी।

नदी बांध योजना का वैज्ञानिक विकल्प है एमएसडीटी टेक

■ इन्द्र चन्द रजवार

जन संघर्ष वाहिनी द्वारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 29 जून 2016 को एमएसडीटी टेक नदी बांध योजना का वैज्ञानिक विकल्प विषय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को एमएसडीटी टेक के शोध कर्ता श्याम सुंदर राठी और जन संघर्ष वाहिनी के संयोजक भूपेंद्र सिंह रावत ने संबोधित किया। शोधकर्ता श्याम सुंदर राठी ने कहा कि नदी बांध योजना बाढ़ से बचाव और जल भंडारण का यह अब तक एकमात्र माध्यम रहा है। यह तरीका लगभग 5000 वर्ष पुराना है। हमारे पूर्वजों ने नदी घाटियों में जल भंडारण करना आरंभ किया था। हम आज तक बाढ़ नियंत्रण, जल भंडारण और प्रदूषण रहित जल विद्युत उत्पादन के लिए उसी प्रणाली का अनुसरण करते आए हैं। वर्तमान नदी बांध योजना बाढ़ नियंत्रण और जल भंडारण की हमारी जरूरतों को पूरा करने लिए पर्याप्त नहीं है।

श्री राठी ने कहा कि मल्टी स्टोरी डिस्टेंस टैंक टेक्नोलॉजी (एमएसडीटी टेक) नदी बांध योजना का वैज्ञानिक विकल्प है जिससे बाढ़ और सूखे की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है और बहुत ही कम लागत में जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, इससे बिजली उत्पादन कर ऊर्जा संकट की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है

एमएसडीटी टेक के शोधकर्ता श्याम सुंदर राठी और जन संघर्ष वाहिनी के संयोजक भूपेंद्र सिंह रावत

और विश्व को ताप (थर्मल) एवं न्यूक्लीयर ऊर्जा संयत्रों और जल विद्युत परियोजनाओं से होने पर्यावरण प्रदूषण एवं पारिस्थितिकी असंतुलन से मुक्त किया जा सकता है। इससे नदी घाटी जल विद्युत परियोजनाओं की तरह विस्थापन की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। एमएसडीटी टेक प्रणाली के माध्यम से जल भंडारण की बड़ी से बड़ी योजना को एक से तीन साल अंदर तैयार किया जा सकता है। इसी तरह ओवर हेड पावर जनरेशन प्रणाली से हम 20 दिनों के अंदर बिजली उत्पादन शुरू कर सकते हैं, जो वर्तमान जल विद्युत उत्पादन प्रणाली के ठीक विपरीत है।

इस मौके पर जन संघर्ष वाहिनी के संयोजक भूपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि एमएसडीटी टेक के तहत एक बड़ी परियोजना का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया गया है, जिसमें 1500 घन किमी पानी का भंडारण किया जाएगा। ●

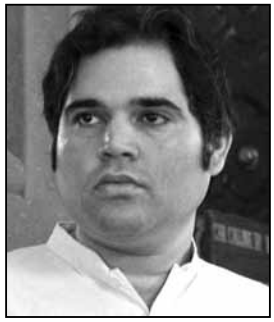
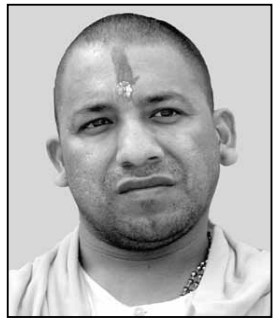

इनकी किस्मत इस बार भी नहीं खुली

उन्हें आस थी कि मोदी मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार में उनका नाम जरूर होगा, लेकिन निराशा हाथ लगी तो कुछ कोपभवन में चले गए, कुछ ने बगावती रुख अख्तियार कर लिया है।

2014 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही भाजपा के कई नेताओं ने अपनी नजर कुर्सी पर गढ़ा रखी थी, लेकिन जब उन्हें कुर्सी नहीं मिली तो उनके ताजा-ताजा खिले दिल मुरझा गए, हालांकि कुर्सी पाने की उनकी आस तब भी खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया, लेकिन इस बार भी उनका नाम लिस्ट में नहीं था, तो उनका दिल धक् से बैठ गया। उन्होंने सोचा अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार आगे फिर होगा, तब उनका नाम जरूर होगा। इस बीच वे सेटिंग-गेटिंग में लग गए। इधर मोदी जी ने नए विस्तार में अपने मंत्रिमंडल को जम्बोजेट बना दिया, लेकिन उनका नाम तब भी न आया। उनकी हालत अब काटो तो खून नहीं। ऊपर से पत्रकार उनके जले पर ये कहकर नमक छिड़क दे रहे हैं कि ये मंत्रिमंडल का आखरी विस्तार है। ऐसे में उनकी हालत आप समझ सकते हैं। इनमें से कुछ कोपभवन जा चुके हैं, तो कुछ जाने की तैयारी में हैं।

पश्चिमी दिल्ली सीट से सांसद प्रवेश वर्मा से जब भी पत्रकार मिलते थे, तो यही पूछते कि आप मंत्री कब बन रहे हैं? इस सवाल पर प्रवेश यूं सीधे कोई जवाब नहीं देते थे, लेकिन उनका दिल बल्लियों उछल जाता। उन्हें लगता था कि वे एक दिन मोदी मंत्रिमंडल में जरूर होंगे और तब वे उन मंत्रियों को यह बताएंगे कि वास्तव में युवा कौन है, जो 50-55 की उम्र हो जाने के बाद भी अपने को युवा बताते हैं। फिलहाल वे कोपभवन में चले गए हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले वे मोदी मंत्रिमंडल की शोभा जरूर बढ़ाएंगे।

जिस दूसरे युवा को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की पूरी आस थी, वे वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल व पूर्व में भाजपा के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह के सुपुत्र राजवीर सिंह हैं। आखिर-आखिर तक उन्हें यही सूचना मिलती रही कि पिटारे में उनका भी नाम हैं, लेकिन जब पिटारा खुला तो उनका नाम नदारद था। चर्चा है कि वे नाराज होकर अब कोपभवन में चले गए हैं, जबकि उनके पिता ने भी कोपभवन जाने की धमकी देनी शुरू कर दी है। कल्याण सिंह का कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को नाराज करके भाजपा को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के सपने नहीं देखने चाहिए।

यूं वरुण गांधी की मां मेनका गांधी मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन वरुण को लगता है कि गांधी उपनाम जुड़े होने की वजह से उन्हें भी मंत्री बनाया जाना चाहिए। उनके करीबी खुलकर कहते हैं कि भाजपा को गांधी उपनाम की महत्ता का पता नहीं है, वह तो वरुण की मजबूरी है वर्ना वे कांग्रेस में होते तो उनके जलवे ही कुछ और होते। अब उन्हें कौन समझाए कि भाजपा वाले उनकी इस मजबूरी से भलीभांति वाकिफ हैं और वे इसी का फायदा भी उठा रहे हैं। खैर, उनके समर्थक ने अब उन्हें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री घोषित करवाने के लिए अपनी कमर कस ली है।

अपने आपको हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता मानने वाले योगी आदित्यनाथ को भी लगता रहा है कि मोदी उनकी उपेक्षा नहीं होने देंगे, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को भी उन जैसे नेताओं को संभालना बखूबी आता है। हालांकि अब वे भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा का खेल बिगड़ाने की रणनीति बना रहे हैं।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री जरूर बनाया जायेगा, लेकिन उनके अरमानों पर इस बार भी पानी फिर गया। बाबा रामदेव ने भी उनके लिए खूब लॉबिंग की थी। इन दिनों निशंक हरिद्वार के कोपभवन में हैं। इनके अलावा प्रभात झा, विनय कटियार, रमेश बैस जैसे कई नेताओं को भी अपनी लॉटरी लगने का इंतजार था। स्वप्न दासगुप्ता के लिए अरुण जेटली ने खूब लॉबिंग की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के मनोनीत सांसदों में से किसी को मंत्री बनाया ही नहीं।

अलग-थलग पड़ी कांग्रेस

जीएसटी पर कांग्रेस के विरोध के अब कोई मायने नहीं रह गए हैं, इसलिए मानसून सत्र में इस विधेयक के पास होने की पूरी संभावना है।

संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस बार वस्तु एवं सेवा यानी जीएसटी विधेयक पास हो जायेगा। संसदीय मामलों के मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बताया कि जीएसटी देश के हित में है और जीएसटी के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या है, लेकिन हम सभी दलों की सहमति चाहेंगे, क्योंकि इसका राज्यों पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार आम सहमति से इस विधेयक को पास कराना चाहती है और इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद आम सहमति नहीं बनी तो भी हमें इसे मानसून सत्र में ही पास कराना है।

दरअसल, इस बार सरकार के हौसले बुलंद

हैं, क्योंकि कांग्रेस अलग-थलग पड़ गई है। वर्तमान में राज्यसभा में संख्या बल की बात करें, तो 11 जून को 58 सीटों पर हुए चुनाव के बाद भाजपानीत गठबंधन राजद सबसे बड़ा गठबंधन बन गया है। साथ ही, सरकार ने अपनी ओर से सात सदस्यों को नामांकित भी किया। राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। जीएसटी चूंकि संविधान संशोधन बिल है, लिहाजा इसके लिए मतदान के वक्त आधे सदस्यों यानी 123 की उपस्थिति जरूरी है, जबकि बिल पारित कराने के लिए दो तिहाई यानी 164 सदस्यों का समर्थन चाहिए।

बीजेपी के पास अब 54 सांसद हैं। इनमें दो नामांकित सदस्य नवजोत सिंह सिद्धू और सुब्रह्मण्यम स्वामी भी हैं, जो भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा तेलुगुदेशम पार्टी के छह, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना के 3-3, जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक

पार्टी (पीडीपी) के दो सांसद एनडीए में हैं। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, बोडो पीपुल्स फ्रंट, नगा पीपुल्स फ्रंट और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के एक-एक सांसद भी हैं। हरियाणा से निर्वाचित सुभाष चंद्रा के साथ चार निर्दलियों का समर्थन एनडीए को मिलेगा और पांच नामांकित सदस्यों का भी। इस तरह एनडीए का आंकड़ा 81 हो जाता है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी सहित वे तमाम विरोधी दल हैं, जो जीएसटी के पक्ष में खुलकर सामने आ चुके हैं। वामदल भी जीएसटी के पक्ष में आ गई हैं।

ऐसे में, विरोध में सिर्फ कांग्रेस और एआईएडीएमके जैसी पार्टियां ही बचती हैं। इन्हें ज्यादा से ज्यादा एक निर्दलीय और उन पांच नामांकित सदस्यों का साथ मिल सकता है, जिन्हें यूपीए सरकार ने चुना था।

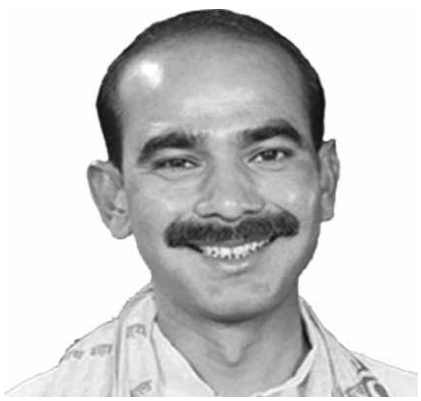

कहावत यूं ही थोड़ी बनाई ठहरी

इस बार तय था कि मोदी मंत्रिमंडल में उत्तराखंड से किसी न किसी को जगह जरूर मिलेगी, लेकिन किसे? इस बारे में दिल्ली से लेकर देहरादून तक अखबारनबीस यही चर्चा छेड़े हुए थे कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री के नाम का लकी ड्रा निकल सकता है। तीन पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी, भगत सिंह कोश्यारी और डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक या किसी और नाम की चर्चा थी तो वह सतपाल महाराज थे। जब विस्तार के दिन करीब आने लगे, तब जाकर कुछ लोगों ने अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा के नाम की चर्चा की, हालांकि तब भी लोगों को यही लगा कि वे पहली बार सांसद बने हैं, इसलिए मोदी उन्हें शायद ही मंत्री बनायें। खैर, अब जब फाइनली टम्टा मंत्री बन गए हैं, तो वही लोग कह रहे हैं कि वो कहावत खाली थोड़ी बनाई ठहरी कि दो चूहों की लड़ाई में बिल्ली बाजी मार ले गई।

■ **ललित पांडे**

'कृषि चौपाल' पत्रिका डाक से मंगाने के लिए सदस्यता फॉर्म

● **एक वर्ष (12 अंक) : रु. 200** ● **दो वर्ष (24 अंक) : रु. 380** ● **पांच वर्ष (60 अंक) : रु. 950**

सदस्य का नाम .....

डाक का पता .....

..... राज्य ..... पिन कोड .....

फोन/मोबाइल ..... ई-मेल .....

चेक/डिमांड ड्राफ्ट संख्या ..... रुपये ..... बैंक व ब्रांच का नाम .....

दिनांक ..... हस्ताक्षर .....

-: कृपया ध्यान दें :-

पत्रिका भारतीय डाक विभाग की पोस्टल सेवा से भेजी जाएगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट '**KRISHI CHAUPAL**' के नाम देय होगा। उसके पीछे अपना नाम, पता एवं फोन नंबर लिखकर नीचे दिये गये पते पर भेजें:-

कृषि चौपाल, सी-355, तृतीय तल, गली नं.-9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092, फोन: +91-991040-6059

सुमीता प्रवीण केशवा
सचिव, हिंदी विभाग,
जेजेटी विश्वविद्यालय

पहाड़ की औरत

जीने की जद्दोजहद में पहाड़ के सीने को चीरती
वह पहाड़ी औरत रोज मुठभेड़ करती है पहाड़ों से
हाथों में कुल्हाड़ी व कमर में दरांती खोसकर
चढ़ जाती है पहाड़ों की छाती पर पुरुष बनकर
बटोर लाती है घर भर की खुशियां
अपने सिर पर रखे बड़े से घास के गठ्ठर में
जब गाय-भैंस खाएंगी घास-फूस
तो देंगी ढेर सारा दूध
होगी दही-धिनाली, खाएंगे बच्चे
होगी खुशहाली...

गंगा सी पावन भोली-भाली मुस्कान लिए
वह पहाड़ की औरत नहीं जानती है अभी
शहरी औरतों की मानिंद आजादी के नए-नए नुस्खे
अपनी देह के सौंदर्य से बेखबर पहाड़ी औरत
नहीं जानती अभी देह षड्यंत्र की परिभाषा
कोसों दूर है अभी उसके लिए देह की आजादी के मायने
उसे कोई सरोकार नहीं देह की आजादी से
उसे तो चाहिए सिर्फ भूख से आजादी...

आज भी उसकी दरांती और कुल्हाड़ी से
सुनाई पड़ती है भूख से आजादी के लिए धमक।

एक किसान की कहानी...

एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया! कभी बाढ़ आ जाये, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जायें! हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाये! एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, 'देखिये प्रभु,आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेतीबाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिये। जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भण्डार भर दूंगा!'

परमात्मा मुस्कराये और कहा, 'ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा!'

किसान ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाही, तब धूप मिली, जब पानी तब पानी! तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी! किसान ने मन ही मन सोचा अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे।

फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया। लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रख कर बैठ गया! गेहूं की एक भी बाली के अन्दर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अन्दर से खाली थीं। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, 'प्रभु ये क्या हुआ?'

तब परमात्मा बोले, 'ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा-सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी-ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का अहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है, वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है!'

उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अन्दर कोई गुण नहीं आ पाता! ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जायेंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा!

यारशागुंबा यानी कीड़ा-जड़ी

हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में एक नायाब जड़ी मिलती है 'यारशागुंबा' जिसका उपयोग भारत में तो नहीं होता लेकिन चीन में इसका इस्तेमाल प्राकृतिक स्टीरॉयड की तरह किया जाता है। शक्ति बढ़ाने में इसकी करामाती क्षमता के कारण चीन में ये जड़ी खिलाड़ियों खासकर एथलीटों को दी जाती है। इस जड़ी की यह उपयोगिता देखकर पिथौरागढ़ और धारचूला के इलाकों में बड़े पैमाने पर स्थानीय लोग इसका दोहन और तस्करी कर रहे हैं क्योंकि चीन में इसकी मुंहमांगी कीमत मिलती है।

सामान्य तौर पर समझें तो यह एक तरह का जंगली मशरूम है जो एक खास कीड़े की इल्लियों यानी कैटरपिलर्स को मारकर उस पर पनपता है। इस जड़ी का वैज्ञानिक नाम है कॉर्डिसेप्स साइनेसिस और जिस कीड़े के कैटरपिलर्स पर ये उगता है उसका नाम है हैपिलस फैब्रिकस। स्थानीय लोग इसे कीड़ा-जड़ी कहते हैं क्योंकि ये आधा कीड़ा है और आधा जड़ी है और चीन-तिब्बत में इसे यारशागुंबा कहा जाता है।

ये जड़ी 3500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में पाई जाती है जहां ट्रीलाइन खत्म हो जाती है, यानी जहां के बाद पेड़ उगने बंद हो जाते हैं। मई से जुलाई में जब बर्फ पिघलती है तो इसके पनपने का चक्र शुरू हो जाता है। बताया जाता है कि 3-4 साल पहले जहां ये फंगस चार लाख रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकता था वहीं अब इसकी कीमत 8 से 10 लाख प्रति किलोग्राम हो गई है।

वैज्ञानिकों के अनुसार इस फंगस में पोषक तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं। ये तत्काल रूप में ताकत देते हैं और खिलाड़ियों का जो डोपिंग टेस्ट किया जाता है उसमें ये पकड़ा नहीं जाता। चीनी-तिब्बती परंपरागत चिकित्सा पद्धति में इसके कई उपयोग हैं। कीड़ा-जड़ी से आजकल यौन उत्तेजना बढ़ाने वाले टॉनिक भी तैयार किए जा रहे हैं जिनकी भारी मांग है। ●

शुभकामनाएं

जी. एस. रावत

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हॉइथ्रो इंजीनियर्स प्रा. लि.
सुप्रीम एडवरटाइजिंग प्रा. लि.
हैंनक्राफ्ट एक्सपो डिजाइन प्रा. लि.

302, 303 भीकाजी कामा भवन
11, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
फोन: 011-26186038, 26180238

hythroengineers@airtelmail.in
supremeadvertising@airtelmail.in

RNI Regd. No. DELHIN/2007/20953 Postal Regd No.: DL(E)-20/5505/2016-18 Date of Posting: 11-12 Same Month

MADE EASY

MADE EASY

India's Best Institute for IES, GATE & PSUs

Crack in 1st Attempt

ESE, GATE & PSUs

• Best Faculty • Best Study Material • Best Results

Why most of the students prefer MADE EASY !

Comprehensive Coverage
- More than 1000 teaching hours
- Freshers can easily understand
- Emphasis on fundamental concepts
- Basic level to advance level
- Coverage of whole syllabus (Technical and Non technical)

Focused and Comprehensive Study Books
- Thoroughly revised and updated
- Focused and relevant to exam
- Comprehensive so that, there is no need of any other text book
- Designed by experienced & qualified R&D team of MADE EASY

Dedication and Commitment
- Professionally managed
- No cancellation of classes
- Pre-planned class schedule
- Starting and completion of classes on time
- Subjects completion in continuity
- Co-operation and discipline

Complete guidance for written and personality test
MADE EASY has a dedicated team which provides round the year support for
- Interpersonal Skills
- GD and Psychometric Skills
- Communication Skills
- Mock Interviews

Motivation & Inspiration
- Motivational Sessions by experts
- Expert Guidance support
- Interaction with ESE & GATE toppers

Regular updation on Vacancies/Notifications
- Display on notice board and announcement in classroom for vacancies notified by government departments
- Notification of ESE, GATE, PSUs and state services exams

Professionally Managed & Structured Organization
- MADE EASY has pool of well qualified, experienced and trained management staff

Best Pool of Faculty
- India's best brain pool
- Full time and permanent
- Regular brain storming sessions and training
- Combination of senior professors and young energetic top rankers of ESE & GATE

Consistent, Focused and Well planned course curriculum
- Course planning and design directly under our CMD
- GATE & ESE both syllabus thoroughly covered
- Course coordination and execution directly monitored by our CMD

Best Infrastructure & Support
- Well equipped audio-visual classrooms
- Clean and inspiring environment
- In campus facility of photocopy, bookshop and canteen
- Best quality teaching tools

Regular Assessment of Performance
- Self assessment tests (SAT)
- ESE all India Classroom Test Series
- GATE Online Test Series
- Subject-wise classroom tests with discussion
- Examination environment exactly similar to GATE & UPSC exams

Counseling Seminars and Guidance
- Career counseling
- Post GATE counseling for M.Tech admissions
- Techniques for efficient learning
- Full Time Interview support for IES & PSUs

Timely completion of syllabus
- 4-6 hrs classes per day
- Well designed course curriculum
- Syllabus completion much before the examination date

Maximum Selections with Top Rankers
- MADE EASY is the only institute which has consistently produced Toppers in IES, GATE & PSUs
- Largest Selections in GATE
- Largest Selections in IES

Audio Visual Teaching | Hostel Support | Safe, Secured and Hygienic Campus Environment

Courses offered at MADE EASY

- Regular/Weekend/Super Talent Batches
- Rank Improvement Batches
- Online Test Series
- Postal Study Course
- MADE EASY Books
- Interview Guidance Program

Selections from MADE EASY in GATE 2016 & ESE 2015

MADE EASY Students Top in ESE-2015: 38 Selections in Top 10 | 351 Selections out of total 434 | MADE EASY selections in ESE-2015 82% of Total Vacancies

MADE EASY Students Top in GATE-2016: 53 Selections in Top 10 | 368 Selections in Top 100 | 1st Rankers in 6 Streams ME • EE • EC • IN • CS • PI

Streams: CE ME EE EC CS IN PI

For more details, visit : www.madeeasy.in

Delhi	Noida	Lucknow	Jaipur	Bhopal	Indore	Pune	Hyderabad	Bhubaneswar	Kolkata	Patna
011-45124612	0120-6524612	09919111168	0141-4024612	0755-4004612	0731-4029612	020-26058612	040-66774612	0674-6999888	033-68888880	0612-2356615
09958995830	08860378009	08400029422	09166811228	08120035652	07566669612	09168884343	040-24652324	09040999888	08282888880	09955991166

Corporate Office: 44-A/1, Kalu Sarai (Near Hauz Khas Metro Station) New Delhi-110016; Ph: 011-45124612